● वर्ष-4
● अंक-17
रायपुर, गुरुवार
29 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

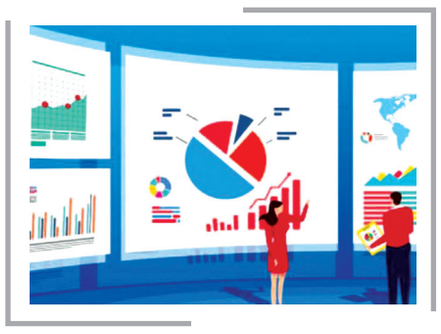

पेज-6›› बाजार के बदलते मिजाज पर रखिए..

नक्सल प्रभावितों को शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण

शेष जिलों के विद्यार्थियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ऋण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना' के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने कहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख निर्धारित है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको मोरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।

राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों में छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रवेशित हो। अधिकतम पारिवारिक आय रूपये 2 लाख होनी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख है।

ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप ऑउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।

इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ

योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए, डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है।

जिन्ना की तरह ही समाज को बांटने का कार्य कर रही है कांग्रेस-सपा - योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, इसलिए वह अंतिम समय में घुट-घुट कर मरा था। समाज को बांटकर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जब देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तब ये लोग समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद से देश नई बुलंदियों की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ समूचा विपक्ष समाज में जाति का विष घोल कर अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा है।

सीएम योगी ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कारनामे किए आज उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज पसंद नहीं आ रहा है। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कहते थे कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है। यही लोग हैं जो बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे।

सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बेटी और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए यमलोक का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अयोध्या, कन्नौज और कोलकाता की घटना पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों को जब भी सत्ता प्राप्त हुई तो सामाजिक ताने-बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया।

चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। वे 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। अपने इस्तीफे को एक्स पर पोस्ट करते हुए चंपई सोरेन ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्याग पत्र दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूल वासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र में लिखा कि आदरणीय गुरु जी, जोहार। मैं चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से विक्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने को विवश हूं। अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप के मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था एवं जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों एवं गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है।

उन्होंने लिखा कि झामुमो मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा एवं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ यह कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है।

उन्होंने पत्र में लिखा कि आपके वर्तमान स्वास्थ्य की वजह से आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं तथा आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है, जहां हम अपनी मन की पीड़ा को बता सकें। इस वजह से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। आपके मार्गदर्शन में झारखंड आंदोलन के दौरान तथा उसके बाद भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें।

हाल ही में चंपई ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। चंपई सोरेन सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे थे जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बीते मंगलवार के बाद से यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने झामुमो के पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही नया विकल्प भी तलाशने की बात कही थी। बाद में ये चर्चाएं भी हुईं कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। आखिरकार अब चंपई भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं।

रेलवे देश की जीवन रेखा, इसे राजनीति का विषय न बनाएं

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटनाओं को लेकर कहा कि राष्ट्रीय परिवहन को राजनीतिक दोषारोपण का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की जीवन रेखा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ घटनाओं में कुछ परेशान करने वाली स्थिति सामने आई हैं और रेलवे सभी घटनाओं की विस्तृत जांच कर रहा है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे पटरियों पर पत्थर और छड़ रखे जाने के कारण ट्रेनों के पटरी से उतरने की घटनाओं पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, कुछ घटनाओं में कुछ परेशान करने वाली प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने आगे कहा कि रेलवे और रक्षा ऐसे संगठन हैं जिन्हें राजनीति से ऊपर होना चाहिए। मेरा मानना है कि रेलवे को राजनीतिक दोषारोपण का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है और अगर कुछ भी नकारात्मक होता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि ट्रेनें बहुत कुशल तरीके से चले।

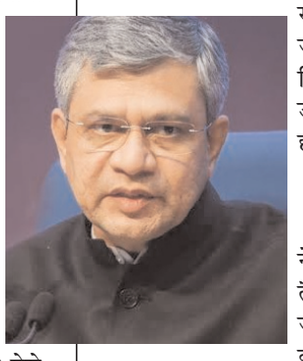

अगले पांच वर्षों में पूरी होंगी सभी स्वीकृत रेलवे परियोजना

वहीं एक अलग सवाल के जवाब में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पिछले एक साल के दौरान मौजूदा नेटवर्क में 5,300 किलोमीटर रेलवे लाइन जोड़ी है। दस साल पहले, रेलवे में निर्माण की औसत गति चार किलोमीटर प्रतिदिन थी। आज, यह 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन है। उन्होंने कहा, सभी स्वीकृत रेलवे परियोजनाएं अगले पांच वर्षों में पूरी हो जाएंगी।

सरकार ने तैयार किया एक भर्ती कैलेंडर- वैष्णव

जबकि रेलवे में भर्ती पर, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर में रिक्तियों को भरने के लिए एक भर्ती कैलेंडर तैयार किया है। चार तिमाहियों को रोजगार की एक विशेष श्रेणी से जोड़ा गया है। पहली तिमाही - जनवरी से मार्च - लोको पायलटों की भर्ती के लिए निर्धारित की गई है, दूसरी तिमाही तकनीशियनों और जूनियर इंजीनियरों को काम पर रखने के लिए, तीसरी तिमाही गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए और चौथी तिमाही लेवल-1 अधिकारियों के लिए आरक्षित की गई है।

रोजगार की वार्षिक योजना तैयार- वैष्णव

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रोजगार की वार्षिक योजना तैयार की गई है और वर्तमान भर्ती चक्र के लिए 45,000 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया है। मंत्री ने कहा कि पिछले भर्ती चक्र में रेलवे में 1.54 लाख लोगों को रोजगार दिया गया।

प्रमुख समाचार

ममता बनर्जी पर भड़क गए हिमंता बिस्वा सरमा

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन और बांग्लादेश संकट के बीच समानता बताते हुए पड़ोसी राज्य का उल्लेख किया। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि अगर बंगाल जलता है, तो असम और दिल्ली भी जलेंगे वाले बयान को लेकर हिमंत सरमा ने कहा कि तृणमूल प्रमुख अपनी असफलता की राजनीति से भारत में आग लगाने की कोशिश कर रही हैं। सरमा ने कहा कि दीदी (ममता बनर्जी), आपकी असम को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? हमें अपनी खून भरी आंखें मत दिखाओ। अपनी विफलता की राजनीति से भारत को आग लगाने की कोशिश मत करो। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि विभाजनकारी भाषा बोलना आपको शोभा नहीं देता। असम से बीजेपी नेता पीयूष हजारिका ने भी बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमें धमका नहीं सकती, धमकी नहीं दे सकती। मैं उसकी गंभीरता से निंदा करता हूं। वह अपने राज्य में कानून-व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकती और हमें धमकी दे रही है।

भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी को दी चुनौती

नई दिल्ली। सत्तारूढ़ भाजपा की हरियाणा इकाई ने बुधवार को कांग्रेस को राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कुमारी शैलजा को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी, ताकि यह साबित हो सके कि वह एससी समुदाय की भलाई के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। राज्य भाजपा ने यह भी कहा कि वे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नामित करते हैं, जो ओबीसी वर्ग से हैं। सैनी 1 अक्टूबर को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी हैं। हरियाणा बीजेपी ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया कि भाजपा पहले ही पिछड़े वर्ग से एक मुख्यमंत्री को नामांकित कर चुकी है। राहुल गांधी एससी समुदाय का पुरजोर समर्थन करने का दावा करते हैं। उन्हें (कांग्रेस) शैलजा जी को हरियाणा से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने दीजिए ताकि पता चल सके कि वे (एससी) समुदाय के कितने हितैषी हैं। आपको बता दें कि शैलजा, जो सिरसा से लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस का एक प्रमुख दलित चेहरा हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिन्हें शैलजा का कट्टर विरोधी माना जाता है, ने हाल ही में कहा था कि वह न थके हैं।

पाक में महिलाओं को प्रत्याशी नहीं बना पा रहे राजनीतिक दल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने आठ फरवरी को देश में हुए आम चुनावों में पांच फीसदी महिलाओं को प्रत्याशी न बनाने पर राजनीतिक दलों को तलब किया है। आयोग ने चार सितंबर को राजनीतिक दलों के नेताओं को पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कानून का पालन न करने पर जमात-ए-इस्लामी (जेआई), अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी), बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी), तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) समेत 10 अन्य पार्टियों के प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान में चुनाव अधिनियम की धारा 206 के तहत आम चुनाव और प्रांतीय विधानसभा चुनावों में सामान्य सीटों पर कम से कम पांच फीसदी महिलाओं को प्रत्याशी बनाना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने इस मुद्दे को लेकर पार्टी के नेताओं को चार सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। आठ फरवरी को देश में हुए चुनावों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से 93 पर जीत हासिल की थी।

पीएसयू कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को केंद्र सरकार और पीएसयू बैंकों के कुछ कर्मचारियों को बचाने के लिए आगे आया, जिन्हें इस आधार पर नौकरी से निकाले जाने का खतरा था कि उनकी जाति, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा गया था, बाद में कर्नाटक सरकार की तरफ से उन्हें अनुसूचित जाति से हटा दिया गया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा, हम मानते हैं कि अपीलकर्ताओं को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने में प्रतिवादी बैंकों/उपक्रमों की प्रस्तावित कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है। के निर्मला समेत कोटेगारा अनुसूचित जाति और कुरुबा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को उनके संबंधित नियोक्ताओं - केनरा बैंक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जारी किए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। पीएसयू नियोक्ताओं ने कहा था कि इन कर्मचारियों की जातियां और जनजातियां अब एससी और एसटी का हिस्सा नहीं हैं.

जीएनएसएस-रिफ्लेक्टोमेट्री उपकरण ने अंतरिक्ष में शुरू किया काम

बंगलूरू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को बताया कि ईओएस-08 उपग्रह पर जीएनएसएस-रिफ्लेक्टोमेट्री (जीएनएसएस-आर) उपकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। यह भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित रिसीवर है, जिसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी-इसरो) ने विकसित किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने 16 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस-08 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यह उपग्रह छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी-डी3 पर सवार हुआ था। उपग्रह पर लगे जीएनएसएस-रिफ्लेक्टोमेट्री (जीएनएसएस-आर) उपकरण ने 18 अगस्त से अपना काम करना शुरू कर दिया है। जीएनएसएस-आर भारत का पहला अंतरिक्ष में स्थापित रिसीवर है, जो पृथ्वी की सतह से लौटे सिग्नल को मापता है। यह उपकरण एसएसी-इसरो ने विकसित किया है और यह नई तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी की विभिन्न सतहों की जानकारी प्रदान करता है।

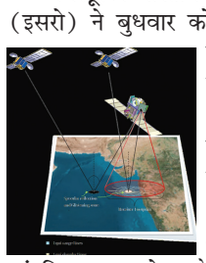

छत्रपति प्रतिमा का ढहना शासन-तंत्र की भ्रष्टता का प्रमाण

ललित गर्ग

मराठा पहचान और परम्परा के प्रतीक पुरुष, प्रथम हिन्दू नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गयी 35 फीट ऊंची प्रतिमा का थरथरा कर गिर जाना राष्ट्रीय शर्म एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार का दु:खद अध्याय है। इस तरह हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी इस प्रतिमा का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में जिस तीव्रता से व्याप्त है, उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है, जो सरकार की साख को धुंधला रही है, यह घटना भारतीय नौसेना की साख को भी बट्टा लगा रही है, यह घटना इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि इससे हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कलई खुल गई है। गौर कीजिए, इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया था।

सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा के गिर जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आना स्वाभाविक है, इससे लोगों का आहत होना भी उचित हैं। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के महानायक एवं जन-जन की आस्था के केन्द्र हैं। वे महाराष्ट्र के जीवन का अभिन्न अंग हैं एवं वहां की राजनीति उनके नाम के इर्द-गिर्द घूमती है। महाराष्ट्र ही नहीं सम्पूर्ण देश में शिवाजी महाराज के प्रशंसक हैं। मराठों के अस्तित्व एवं अस्मिता के वे प्राण रहे हैं, मराठों को उन्होंने ने ही लड़ना सिखाया, उनके जीवन को उन्नत बनाया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महाराष्ट्र की सभी जातियों को एक भगवा झंडे के नीचे एकत्रित किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपने राज्य-शासन में

मानवीय नीतियां अपनाई थी जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। महाराष्ट्र क्योंकि उनकी जन्मस्थली ही नहीं कर्मस्थली भी रहा इसलिए महाराष्ट्र की आबोहवा में वे आज भी जीवंत हैं। ऐसे महानायक की प्रतिमा के गिर जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। मूर्ति का निर्माण और डिजाइन नौसेना ने तैयार किया था। कहा तो यही जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण प्रतिमा टूटकर गिर गई।

छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र और मराठा संस्कृति के ही नहीं, बल्कि भारतीयता के प्रतीक एवं प्रेरणा पुरुष हैं। आम मराठी भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा है। ऐसे में, इस मूर्ति का ढहना राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार एवं भारतीय नौसेना की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। चंद महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने के कारण यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनना निश्चित है। एक मजबूत विपक्षी पार्टी शिव सेना की पूरी राजनीति शिवाजी के शौर्य व आत्म-गौरव से प्रेरित है, एनसीपी शरद पवार, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था और इस काम में गुणवत्ता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। प्रतिमा का ढह जाना छत्रपति शिवाजी का अपमान तो है ही और यह जाहिर है कि इसका काम घटिया गुणवत्ता का था। इसीलिये घटना को शिवाजी के अपमान के रूप में पेश किया जाने लगा है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवाजी की प्रतिमा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। इस मुद्दे को वोट जुटाने के लिए असरदार हथियार के रूप में जरूर इस्तेमान किया जायेगा। लेकिन मूल प्रश्न है ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कब सार्थक प्रयास होंगे? राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि न सिर्फ विपक्ष के आरोपों की धार को निस्तेज किया जा सके, बल्कि सार्वजनिक निर्माण में किसी किस्म की लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों को भी यह संदेश मिल सके कि वे बख्शे नहीं जाएंगे।

यह पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी बड़ी निर्माण योजना की कमी इस तरह की भ्रष्ट एवं लापरवाही के रूप में उजागर हुई है। हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बार-बार तार-तार होती रही है। मई 2023 में उज्जैन के महालोक कोरिडोर में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां भी इसी तरह आंधी-तूफान में धराशायी हो गई थीं। अयोध्या में भी सड़के ध्वस्त हो गयी थी। बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे-बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं हैरान करने के साथ-साथ चिंतित करने वाली बनी हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल-1 पर छत गिरने की घटना से भी हर कोई हैरान हुआ है। मुंबई में घाटकोपर का होर्डिंग गिरना 14 लोगों की मौत का कारण बना था। कहीं नई बनी सड़कें धंस हो जाती हैं तो कहीं नई सरकारी इमारतों में दरारे पड़ जाती है। इन मूर्तियों, पुलों, सड़कों एवं सार्वजनिक निर्माण के अन्य सरकारी निर्माणों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चरमरा गई है, दोषग्रस्त हो गई है।

जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और अमानवीय व्यवहार पर हाईकोर्ट सख्त

डीजीपी को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और उनके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर डीजीपी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जानकारी देने कहा है। मामले में तीन जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई हो रही है।

केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने एक जनहित याचिका लगाई है। कुछ समय बाद जेलों में कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन दो जनहित याचिकाओं के अलावा हाई कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की स्थिति को लेकर स्वत- संज्ञान में लिया और जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की।

तीनों जनहित याचिका की एक साथ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है। मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया था। पूर्व की सुनवाई में शासन ने बताया था कि, जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं को लेकर काम किया जा रहा है। रायपुर व बिलासपुर के सेंट्रल जेलों में विशेष जेलों की स्थापना व बेमेतरा में ओपन जेल जल्द प्रारंभ करने की जानकारी राज्य शासन ने दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुनील पिल्लै ने बताया कि जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पहले आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का देश के सभी राज्यों में पालन किया जाना था, लेकिन प्रदेश के जेलों में वर्तमान स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। जिस पर कोर्ट ने डीजीपी से शपथ पत्र में जवाब मांगा है, जिसमें इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कितना परिपालन किया जा रहा है।

मां को गुजारा भत्ता दिए जाने के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गया बेटा

बिलासपुर। पति की मौत के बाद मां ने बेटे से गुजारा भत्ते के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई, जहां बेटे को हर माह 15 हजार रुपए गुजारा भता देने के आदेश दिया गया था, बेटे ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने बेटे की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की वजह से ही उसने यह खूबसूरत दुनिया देखी है। वृद्धा मां को गुजारा भत्ते से वंचित करना कानून ही नहीं, नैतिकता के भी खिलाफ होगा।

■ कोर्ट ने कहा- भत्ते से वंचित करना कानूनन ही नहीं बल्कि नैतिकता के भी खिलाफ

दरअसल, जगदलपुर में रहने वाली सुनीला मंडल के पति एसपी मंडल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के कर्मचारी थे। जो वर्ष 2007 में रिटायर हुए। एनएमडीसी की नीति के मुताबिक उन्हें 4 हजार रुपए पेंशन मिल रहा था। वर्ष 2017 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद सुनीला मंडल को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके दोनों बेटे उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे। दो साल तक परेशान होने के बाद वर्ष 2019 में जगदलपुर के फैमिली कोर्ट में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन लगाया, और बड़े बेटे संजय कुमार मंडल को गुजारा भत्ता देने के निर्देश देने की मांग की।

उन्होंने कोर्ट को दिए अपने आवेदन में बताया, कि वे गृहिणी हैं। वर्तमान में पति द्वारा बनवाए गए मकान में रह रही हैं। बड़ा बेटा 2008-09 से एनएमडीसी में काम कर रहा है, और छोटा बेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोकापाल में रेडियोग्राफर है। उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी देखभाल, इलाज आदि के लिए आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने मां की अर्जी मंजूर करते हुए हर माह 15 हजार रुपए देने के आदेश दिए थे। जिस पर बेटे ने हाई कोर्ट में पहले पुनरीक्षण अर्जी लगाकर बताया कि उसे हर माह 55 हजार रुपए सैलरी मिलती है। जिसमें से कार लोन के लिए 9 हजार, होम लोन के 14 हजार, बीमा के लिए 20 हजार रुपए देने पड़ते हैं। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फरवरी 2020 को सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन पेश करने की छूट देते हुए इसे निराकृत कर दिया था। इसके बाद बेटे ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बेटे की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कहा है कि बेटा किसी भी तरह के विचार के आधार पर वैधानिक दायित्व से छूट नहीं मांग सकता। बेटे की यह सोच घरों की ढहाने, मूल्यों को कमजोर करने, परिवारों को खत्म करने और हमारी भारतीय संस्कृति की नींव को तोड़ने का काम करेगा। कंप्यूटर युग में यह निराशा और विनाश का संदेश है, जिसमें आशा का एक भी शब्द नहीं है। माता-पिता बच्चे को नाम, स्थान, सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान देते हैं। बच्चे को उस समाज से जोड़ते हैं जिसमें वह रहेगा, बड़ा होगा।

नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर पुलिस जवान के भाई की दिनदहाड़े हत्या की

बीजापुर। नक्सलियों ने एक बार फिर मुखबिरी के आरोप में एक ग्रामीण की हत्या कर दी। नक्सलियों ने पुलिस जवान के भाई को दिनदहाड़े धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने पिछले चार दिनों में तीन हत्या की घटनाओं को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की हैं।

जानकारी के मुताबिक, मिरतुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिमेनार में नक्सलियों ने एक पुलिस जवान के भाई कारम सुदरु की दिनदहाड़े धारदार हथियार से वार कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी है। नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में ग्रामीण की हत्या की हैं। बताया गया है कि ग्रामीण पटेलपारा तिमेनार में रहता था। मृतक का भाई पुलिस जवान है और वह दंतेवाड़ा में पदस्थ हैं। बता दें कि बीते शनिवार की रात नक्सलियों ने गंगालुर थाना क्षेत्र के पुसनार में एक ग्रामीण लांचा पुनेम की मुखबिरी के शक में धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी।

वहीं, सोमवार को जांगला थाना के जैगुर निवासी ग्रामीण मंडावी सीतु की नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में जनअदालत लगाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और अब मिरतुर थाना क्षेत्र के तिमेनार में नक्सलियों ने पुलिस जवान के भाई को मौत के घाट उतार दिया हैं।

बलरामपुर में महिला वन रक्षक पर रिश्वत मांगने का आरोप

वीडियो देखने के बाद डीएफओ ने दिया जांच का आदेश

बलरामपुर। राजपुर फॉरेस्ट रेंज में पदस्थ एक महिला वन रक्षक पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। महिला वनरक्षक के रिश्वत लेने का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है।

पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर फॉरेस्ट रेंज का है। जानकारी के मुताबिक विद्यासागर गुप्ता नाम का व्यक्ति वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर खेती करने के लिए जुताई कर रहा था। इस दौरान क्षेत्र भ्रमण पर निकली महिला वन रक्षक ने उसे देखा और वनभूमि पर अतिक्रमण करने की बात कहते हुए ट्रैक्टर जब्त कर लिया। ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में महिला वन रक्षक सुनीता कुजूर और अन्य ने उससे रुपयों की डिमांड की।

विद्यासागर गुप्ता जब पैसे लेकर वन रक्षक को देने के लिए पहुंचा तो महिला वन रक्षक एक गाड़ी में बैठी हुई थी। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि इस वीडियो में महिला वन रक्षक पैसे लेते हुए नहीं दिख रही है। इस मामले की शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की गई। जिसके बाद डीएफओ ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

महिला वनरक्षक के रुपये मांगने के आरोप और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बलरामपुर जिले के डीएफओ अशोक तिवारी का कहना है कि वन परिक्षेत्र राजपुर में एक महिला वन रक्षक की तरफ से अतिक्रमण के एवज में पैसे लेने की शिकायत मिली है। उसी से संबंधित वीडियो है। संबंधित एसडीओ को जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के खिलाफ लगाई कलेक्टर से गुहार

20 रुपए में बेचता है 17 रुपये का शक्कर

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के ग्राम पंचायत अड़भार स्थित उचित मूल्य दुकान के संचालक शारदा महिला स्व सहायता समूह के विक्रेता राजेन्द्र चौधरी पर राशन सामग्रियों की कालाबाजारी और ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय राशन कार्ड धारकों ने आरोप लगाया है कि संचालक निर्धारित शासकीय मूल्य से अधिक वसूली कर रहा है और राशन सामग्री के वितरण में धांधली कर रहा है। जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है।

स्थानीय राशन कार्ड हितग्राहियों ने उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत अड़भार के विक्रेता राजेन्द्र चौधरी पर कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए बताया कि शक्कर का शासकीय उचित मूल्य दर 17 रुपये निर्धारित है जबकि विक्रेता राजेन्द्र चौधरी इसका रुपये 20 वसूलता है। लगभग 44 राशन कार्ड धारियों को अप्रैल महीने का चना वितरण नहीं किया गया जबकि चने के स्टॉक को ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री कर दिया गया था। स्थानीय हितग्राहियों के चना मांगे जाने पर विक्रेता राजेंद्र चौधरी खुलेआम गाली-गलौच और पीटने की धमकी देता है। शारदा महिला स्व सहायता समूह की अन्य महिला सदस्यों ने भी समूह की अध्यक्ष और अध्यक्ष पति राजेन्द्र चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि संचालक हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट लगाकर अग्रिम रूप से चना और शक्कर को ऑनलाइन काट देता है और पैसे भी वसूलता है, लेकिन राशन देने के बजाय महीनों तक टालमटोल घुमाता रहता है, जिससे हितग्राही खाली हाथ रह जाते हैं और इनके हिस्से का राशन विक्रेता बेच देता है। संचालक की मनमानी से सभी त्रस्त है और कोई भी जानकारी पूछे जाने पर धमकाने का काम करते है। जिसको लेकर राशन कार्ड हितग्राहियों ने तत्काल राशन दुकान के संचालक को हटाने की मांग को लेकर उसके खिलाफ खोला मोर्चा खोल दिया।

छत्तीसगढ़ में गौ-अभयारण्य प्रोजेक्ट पर काम तेज

डिप्टी सीएम बोले- यहीं रखेंगे सड़कों पर बैठे मवेशी

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ सरकार आवारा मवेशियों को लेकर गौ-अभयारण्य प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्रदेश के सड़कों में दिखने वाले इन मवेशियों को गौ-अभयारण्य में रखा जाएगा। आज बुधवार को कबीरधाम जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो मवेशी सड़कों पर बैठे रहे, जिन्हे कोई नहीं रखता, ऐसे मवेशियों को गौ-अभयारण्य में सुरक्षित रखा जाएगा। इन मवेशियों के गोबर से खाद का उत्पादन होगा। इसके लिए एजेंसी तय की जा रहीं है। मेरा मानना है कि गौ-अभयारण्य में छोटे-छोटे बच्चे गाय के साथ खेलने के लिए आएंगे।

डिप्टी सीएम ने बताया कि कबीरधाम जिले के ग्राम पचराही में 2018 से पहले भाजपा शासन काल के दौरान करीब 60 एकड़ भूमि में गौ-अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई। इसी जगह में गौ-अभयारण्य बनाया जाएगा। इसी प्रकार बेमेतरा जिले में भी गौ-अभयारण्य का काम चल रहा है। इन दोनों जगह में निर्माण कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। बता दे कि प्रदेश में सड़कों पर खुले में घूमने वाले आवारा गौवंशों की सुरक्षा और इनसे जुड़े हादसों पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

प्रदेश में गौ वंश को लेकर खुब राजनीति होती है। दरअसल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में गौठान बनाया। लेकिन, इस प्रोजेक्ट की स्थिति खराब रहीं है। तब भाजपा विपक्ष में थी। ऐसे में गोबर घोटाला समेत इस प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब भाजपा की सरकार आ गई है। ऐसे में कांग्रेस ने गौ-वंश को लेकर लड़ाई शुरू कर दी है।

इसी माह कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में गौ-सत्याग्रह किया था। विरोध स्वरूप में गाय को लेकर एसडीएम व कलेक्टोरेट पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मवेशियों के संरक्षण की मांग की थी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

ओवरटेक के चक्कर में बस ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर

बालोद। बालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बस्तर रायपुर नेशनल हाईवे मरकाटोला घाट के पास ओवरटेक करने के चक्कर में कांकेर रोडवेज की बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। जिसमें बस में सवार चार यात्री बुरी तरह घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर सभी का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, पूरी घटना पूर्ण पुरूर क्षेत्र का है। थाना प्रभारी शिशुपाल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में चार लोग घायल हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है। यात्रियों को सुरक्षित बस से निकल गया है। हादसे के चलते सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। ट्रैफिक को कम कराया जा रहा है। मरकाटोला घाट दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहां पर अक्सर हद से होते रहते हैं, क्योंकि यह बस्तर अंचल को राजधानी से जोड़ने का एकमात्र प्रमुख मार्ग है। इसलिए यहां पर यातायात का भी काफी दबाव रहता है। अब तक किसी जगह और आसपास दर्जन भर लोग अपनी जान गवा चुके हैं।

एक को टक्कर मारने के बाद कार ने दूसरी बाइक सवारों को रौंदा

कोरबा। कोरबा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत निहारिका क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला। वाहन ने एक के बाद एक दो बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, तीन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात लगभग नौ बजे एक तेज रफ्तार कार निहारिका की ओर से कोसाबाड़ी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कार ने दो बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। पहले एक बाइक सवार मनोज गिरी और शिव कुमार रौंदते हुए दूसरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद देखते ही देखते राहगीरों के भीड़ एकत्रित हो गई और राहगीरों की मदद से सभी को अस्पताल के लिए रवाना किया गया। वहीं तीन लोगों को गंभीर चोटे आए हैं उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की गई जान

बालोद। दुर्ग से बालोद दल्लीराजहरा की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह 11:20 बजे गुण्डरदेही चैनगंज रेलवे फाटक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम परसाही निवासी जिज्ञासु देवांगन पिता हीरालाल देवांगन उम्र 18 वर्ष गुण्डरदेही चैनगंज रेलवे फाटक से 500 मीटर की दूरी पर कान में एयर फोन लगाकर पटरी क्रॉस कर रहे थे, इसी दरमियान दुर्ग से दल्लीराजहरा की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उनके सिर और हाथ पैर में गंभीर चोटे लग गई। गेटकीपर जामलाल पदोती ने बताया 11.20 बजे दुर्ग से पैसेजर ट्रेन आ रही थी, फाटक बंद था। घटना कैसे हुई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ट्रेन रुकने के बाद पता चला की कोई ट्रेन के सामने आ गया है। उक्त घटना बालोद रूट पर रेलवे फाटक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उनके सर पर गहरा चोट होने के कारण वह तुरंत बेहोश हो गया था।

अस्पताल के बाउंड्रीवॉल पर बैठा दिखा तेंदुआ, लोगों के उड़े होश

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उस समय दहशत फैल गई जब एक तेंदुआ जिला अस्पताल की बाउंड्रीवॉल पर बैठा दिखा। देर रात 12 बजे वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने तेंदुआ देखा। इसका वीडियो बनाया और पुलिस और वन विभाग को तेंदुए के जिला अस्पताल की दीवार पर बैठे हुए देखने की सूचना दी। वीडियो में देख सकते हैं कि तेंदुआ बड़े ही आराम से जिला अस्पताल के बाउंड्रीवॉल पर बैठा हुआ है। अस्पताल की बाउंड्री के उस पार घना जंगल शुरू हो जाता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसी घने जंगल से होता हुआ तेंदुआ अस्पताल तक पहुंचा। अस्पताल में तेंदुआ दिखने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को देखने के बाद तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। जिसके बाद वन विभाग की टीम टॉर्च के सहारे तेंदुए को ढूंढने में जुट गई। चितवा डोंगरी के आसपास तेंदुए के होने की आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों उदंती सीतापुर टाइगर रिजर्व में वन विभाग के ट्रैप कैमरे में तेंदुए के शिकार करने का लाइव वीडियो नजर आया था।

बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। बिलासपुर समेत प्रदेश भर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई चल रही है। मामले में कोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन से पूरी राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शपथ पत्र पर जवाब तलब किया था। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि अतिक्रमण और वाहनों के बेतरतीब चालन और पार्किंग के कारण अधिक परेशानी हो रही है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने कोर्ट में जो शपथपत्र दिया है, उसमें इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में चौक चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी के माध्यम से मानिटरिंग करने की बात कही गई है। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर भी कदम उठाए जा रहे हैं, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ट्रैफिक कर्मी भी लगातार मौजूद रहेंगे।

भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म की प्रधानता की शिक्षा दी : मंत्री बघेल

■ श्री कृष्ण झांकी एवं दही लूट महोत्सव में हुए शामिल

बेमेतरा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म की प्रधानता की शिक्षा दी है। उन्होंने अपनी लीला से हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लडने का संदेश दिया। खाद्य मंत्री श्री बघेल मंगलवार को बेमेतरा जिले अंतर्गत नगर पंचायत नवागढ़ में आयोजित भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण झांकी एवं दही लूट महोत्सव कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उक्त बाते कही। उन्होंने इस दौरान भगवान श्री कृष्ण और हलधर बलराम के प्रति रूप का पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की।

बघेल ने कहा कि श्री कृष्ण प्रकृति प्रेमी थे। जब हम भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो हमें यमुना नदी का किनारा याद आता है, बांसुरी की तान याद आती है और गौ माता का झुंड याद आता है। सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है। पीपल, बरगद आदि वृक्षों को पूजनीय माना गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी माँ के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं। भगवान कृष्ण के प्रति भी हमारी सच्ची श्रद्धा तभी प्रकट होगी, जब हम एक पेड़ मां के नाम लगाकर प्रकृति के प्रति अपना दायित्व पूरा करेंगे।

महोत्सव के दौरान आनंद कंद ब्रजनंदन योगेश्वर श्याम सुन्दर भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई एवं विभिन्न गांवों से आए हुए हरिकीर्तन मंडलियों के द्वारा भजन-कीर्तन भी किया गया। मंत्री बघेल ने दही लूट-हांडी-फोड़ टोलियों का उत्साहवर्धन किया और दही लूट के विजेताओं को पुरस्कार एवं शील्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री कृष्ण सेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल तथा नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

संजय रूंगटा समूह को भिलाई निगम ने भेजा नोटिस

दुर्ग। भिलाई नगर निगम राजस्व वसूली के लिए अपनी कमर कसते हुए दर्जनों एकड़ में फैले शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर अदा करने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। इसके साथ ही गलत स्व-विवरणी को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें संजय और संतोष रूंगटा ग्रुप को ही करोड़ों रुपए का नोटिस जारी किया गया है।

भिलाई के जीडीआर रूंगटा कॉलेज को 23 करोड़ 61 लाख 92 हजार रुपए संपत्तिकर जमा करने का नोटिस भिलाई नगर निगम ने जारी किया है। नोटिस में गलत स्व-विवरणी जमा करने पर पेनाल्टी नहीं लगाई गई। संस्थान ने साल 2004 से अब तक संपत्तिकर जमा नहीं किया है।

बता दें कि 25 एकड़ के कैम्पस पर संजय रूंगटा ग्रुप द्वारा संचालित स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज के अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेज जैसी संस्थाएं संचालित हैं। वहीं 26 एकड़ में फैले जमीन पर संतोष रूंगटा ग्रुप द्वारा इंजीनियरिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जा रहा है। इस कैम्पस की गलत स्व-विवरणी देकर कम सम्पत्तिकर जमा करने पर समूह को नोटिस जारी हुआ है।

इसके अलावा गंगाजली एजुकेशन सोसायटी के चेयरमैन आईपी मिश्रा के शंकराचार्य मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को भी नोटिस जारी हुआ। नोटिस जया मिश्रा, रुद्रांश मिश्रा और नारायणी मिश्रा के नाम से नोटिस जारी हुआ है। इस मामले में पहले निगम के अधिकारियों ने गलत स्व-विवरणी पर 81 हजार रुपए का नोटिस जारी किया था, लेकिन बाद में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा की शिकायत के बाद 3 लाख 99 हजार का नोटिस जारी किया है।

इनके अलावा कई ऐसे बड़े बकायदारों ने पुराने सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया है, और नए साल का सम्पत्तिकर जमा करा रहे हैं। जिसकी शिकायत भी की गई है। निगम कमिश्नर देवेश ध्रुव ने बताया कि ऐसे 150 लोगों को सूची हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। जिससे निगम को सम्पत्ति कर के रूप में करोड़ों रुपए की आय होगी।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री को नुआखाई शोभा यात्रा में शामिल होने का मिला न्योता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से कल

यहां उनके निवास कार्यालय में नुआखाई शोभायात्रा संचालन समिति रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय को नुआखाई पर्व शोभायात्रा के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री को समिति के सदस्यों ने बताया कि आगामी 3 सितम्बर को शाम 5 बजे राजधानी रायपुर के ग्रास मेमोरियल खेल मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रतिनिधिमंडल को नुआखाई पर्व की अग्रिम बधाई देते हुए आमन्त्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवसर पर नुआखाई शोभायात्रा संचालन समिति रायपुर से श्री प्रताप, श्री गोपाल सोना, श्री रघुचंद्र निहाल, श्री जितेन्द्र, श्री गणेश हरपाल, श्री वैष्णव, श्री भरत छुरा जी, श्री चंदु बघेल जी, श्री सुरज, श्री पंकज, श्री राजु, श्री रमन ताण्डी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज होने वाला जनदर्शन स्थगित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज 29 अगस्त को होने वाला जनदर्शन स्थगित कर दिया गया है। जनदर्शन कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में हर सप्ताह गुरुवार को जनदर्शन का आयोजन किया जाता है। जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम जनता की समस्या सुनते हैं। वहीं मौके पर ही अधिकारियों समाधान के भी निर्देश देते हैं। जनदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचते हैं। नागरिकों के समस्या समाधान के बाद उसकी जानकारी भी जनसंपर्क विभाग के पोर्टल में अपडेट की जाती है।

महादेव ऐप से जुड़े हवाला नेटवर्क का मास्टरमाइंड दिनेश व्यास गिरफ्तार

रायपुर। महादेव सट्टा ऐप में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में महादेव ऐप से जुड़े हवाला नेटवर्क के मास्टरमाइंड दिनेश व्यास को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिनेश को उसके पैतृक गांव ब्राह्मणवे से पकड़ा है, गुजरात के पाटन जिले के चांसमा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत है। बतादें कि दिनेश व्यास के खिलाफ 3 जुलाई को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इस गिरफ्तारी से महादेव ऐप को समर्थन देने वाले वित्तीय नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है, जो ऐप के खिलाफ चल रही जांच में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। दिनेश व्यास की गिरफ्तारी के बाद और भी बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।दिनेश व्यास को जल्द ही ट्रांजिट रिमांड पर दुर्ग लाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पैसे की लेनदेन को लेकर नेताजी होटल के संचालक के साथ मारपीट

रायपुर। राजधानी के कटोरा तालाब स्थित नेताजी होटल के संचालक के साथ पैसे की लेनदेन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही। नेताजी होटल संचालक राहुल चंदनानी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मैं नेताजी चौक कटोरा तालाब थाना सिविल लाइन रायपुर में रहता हूं और नेताजी होटल का संचालक हूं। 27 अगस्त को दोपहर करीब 02.45 बजे मैं अपने होटल में बैठा था, तभी संदीप मेघानी और नितेश कुमार दुकान में आए और पुरानी पैसे की लेनदेन की बात को लेकर दोनों ने गाली गलौच किया और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़िता के मुताबिक, सचिन मेघानी, करण बजाज, दीव्यांश सक्सेना, मनोज जोशी, कमल पारेख, याकूब गनी भी अपनी गाड़ी में आया और एकराय होकर मुझसे हाथ मुक्का से मारपीट किए। मारपीट करने से मेरे सिर, बांये हाथ, कंधे एवं सिर के पीछे चोट आई है। इस घटना को जितेन्द्र चंदनानी, किशन चंदनानी, कार्तिक बाघ व अन्य लोगों ने देखा सुना है। बीचबचाव करने आई मेरी मां रजनी देवी चंदनानी के साथ भी वाद विवाद करने लगे। मारपीट के दौरान मेरे हाथ में पहना हुआ चांदी का ब्रेसलेट टूटकर गिर गया है।

बिना अनुमति संचालित निजी चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य विभाग की दबिश

रायपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और मरीजों की सुविधा के लिए बिना किसी वैध अनुमति से संचालित निजी अस्पताल तथा डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं । इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के 12 चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार अवस्थी के मार्गदर्शन में टीम ने दबिश देकर निरीक्षण किया साथ ही नोटिस देकर विधिवत अनुमति लेने की अंतिम चेतावनी दी गई है। सीएमएचओ ने बताया की जिले में इस प्रकार के बिना अनुमति के खोले गए संस्थानों के निरीक्षण हेतु टीम का गठन किया गया है। आज इस टीम द्वारा ही दबिश दी गई।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कहा-

पुलिस अपना काम कर रही, कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो होगी कार्रवाई

रायपुर। मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग एसपी समेत सरकार को आड़े हाथ लिया था। बुधवार को इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। कोई कानून को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी ही।

ओड़िशा दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंगलवार को हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर बयान दिया है।उन्होंने कहा कि सरकार किस बात से डरेगी। पुलिस अपना काम कर रही है। कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी ही।

भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुर्ग एसपी को चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, एसपी दुर्ग और उनके आका ठीक तरह से

समझ लें। सत्ता उलटती-पलटती रहती है, काम ऐसे कीजिएगा कि भविष्य में आंख मिला सकें।

बता दें कि मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले रोकने और सुरक्षा कर्मी से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर भिलाई 3 थाना का घेराव किया था। भिलाई 3 के सिरसा गेट में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, चरोदा, भिलाई, और दुर्ग निगम के महापौर शामिल हुए थे। इस धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस के नगर पालिका कुम्हारी अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर और जामुल थाना के टीआई कपिल पांडेय घायल हो गए।

ऐसे शुरू हुआ विवाद

कुछ दिन पहले मामूली विवाद को लेकर जिम संचालक पुष्पराज सिंह और शकील नामक युवक के बीच मामूली विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने अपने-अपने साथियों को बुलाया और स्थिति हिंसक हो गई। बजरंग दल के नेताओं ने इस घटना के बाद शकील और उसके साथियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं दूसरे दिन 24 अगस्त को बजरंग दल के नेताओं ने शकील और उसके साथीयों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भिलाई 3 सिरसा गेट पर बीच सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिले को भी बजरंग दल के द्वारा रोकने और सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप भी लगा। जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भिलाई 3 थाने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

दुर्ग लाठीचार्ज मामला: महापौर समेत 150 से अधिक नेताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज

दुर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने के विरोध में मंगलवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। इस प्रदर्शन के बाद अब पुलिस ने अब चरोदा मेयर निर्मल कोसरे समेत 150 से अधिक नेताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल, 27 अगस्त को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थकों ने दुर्ग के भिलाई 3 थाने का घेराव किया। इससे पहले भिलाई 3 के सिरसा गेट पर एक बड़ी सभा भी आयोजित की गई। जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं थाने के घेराव के दौरान पुलिस ने

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कांग्रेसी नेता और जनप्रतिनिधि के अलावा पुलिस जवान भी घायल हुए। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुए इस टकराव के बाद अब पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत 150 से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। वहीं नामजद में पुलिस ने मेयर निर्मल कोसरे, मनोज मढरिया और सुजीत बघेल को प्रमुख आरोपी के रूप में शामिल किया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 326/24 धारा 189(2), 190, 221, 132, 121, 324(2) के तहत दो अपराध दर्ज किए है। दुर्ग पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है कि लोग उग्र होकर अचानक थाने की ओर बढ़े, झूमाझटकी करते हुए झंडे लेकर, झंडे की लकड़ी से पुलिस बल पर प्रहार करते हुए थाने के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शनकारियों की ओर से किए गए अपराधिक बल प्रयोग से पुलिस बल के तीन जवानों को चोट आई है। इस के साथ साथ बल संसाधित सामग्री भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस के अनुसार पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचानकर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने अपने बयान में कहा था कि प्रदर्शनकारियों ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी। बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का धरना

विकास उपाध्याय ने कहा - बीजेपी सरकार ने प्रदेश सहित रायपुर को अपराध की ओर झोंका

रायपुर। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक व लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय के नेतृत्व में आज कांग्रेसजनों ने रामनगर के ऐतिहासिक कबीर चौक में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 08 माह की सरकार ने प्रदेश की जनता को उपहार में उनके विश्वास के बदले में सिर्फ अपराध दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार हत्या, लूट, डकैती, चोरी, चैन स्नैचिंग, नशीले पदार्थ का व्यापार, अवैध शराब बिक्री, जुआं, सट्टा सहित जघन्य अपराध प्रदेश की जनता को उपहार में दिया है।

वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रामनगर की सड़कों में खुले आम हत्या हो जाती है उसके बाद अपराधी सोशल मीडिया में उसे लाईव भी वायरल कर देता है, कोई अपराधी का पुलिस कार्यवाही होने से पहले ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती बल्कि उनका उल्टा फोन चला जाता है कि उस पर कोई कार्यवाही न की जाये। वर्तमान सरकार एवं वर्तमान

विधायक आँखों में पट्टी बाँधकर बैठे हुए हैं और वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा रामनगर में पुलिस चौकी खोलने के लिए निविदा तक की प्रक्रिया हो चुकी थी उसको तक वर्तमान विधायक द्वारा अपनी हठधर्मिता के कारण शुरू नहीं होने दे रहे हैं उसी के चलते विगत् दिनों उसी क्षेत्र में जहाँ पर पुलिस चौकी खुलना था हत्या जैसी घटना घट गई। आज इसी के विरोध में एकदिवसीय धरना रामनगर के ऐतिहासिक कबीर चौक में भारतीय जनता पार्टी के सरकार एवं विधायक के कार्यशैली के खिलाफ आम जनता एवं कांग्रेसजनों ने धरना प्रदर्शन किया।

विकास उपाध्याय ने कहा कि दो दिन पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिले को रोका जाता है उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों से धक्का-मुक्की और बद्तमीजी की जाती है, उनके गाड़ी में पथराव किया जाता है और जब इसके विरोध में कल कांग्रेस पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया जाता है तब जिन लोगों ने काफिले को रोकने वालों की शिनाक्त करवाई थी उनको चिन्हित कर उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिले में हुए हमले एवं उनके सुरक्षा में हुए चूक को लेकर कल 3 बजे कांग्रेस के प्रतिनिधि मण्डल डीजीपी से मुलाकात करेंगे। उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार में अपराध करने वालों व अपराध पर पूर्ण नियंत्रण था, जबकि पश्चिम विधानसभा, रायपुर शहर सहित पूरे प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्या हमने यही दिन देखने के लिए इन्हें विधायक चुना था, क्या ऐसी स्थिति लाने के लिए सरकार को चुना था, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आग में झोंकने का काम कर रही है और जनता को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, विधायक सोशल मीडिया में कहते फिर रहे हैं हमने बनाया है हम ही संवारेंगे।

देश में टी.बी को जड़ से खत्म करने के लिए जनजागरूकता आवश्यक है : राज्यपाल

रायपुर। प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत देश में वर्ष 2025 तक टी.बी. रोग जड़ से समाप्त करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। टी.बी. उन्मूलन समुदाय के सहयोग के बिना संभव नहीं है। टी.बी. के प्रति सभी को जागरूक होना होगा। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज टी.बी. उन्मूलन के लिए चलाई जा रही एलाइस परियोजना के राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम में उक्त बाते कही।

रीच संस्था के सहयोग से छत्तीसगढ़ सहित देश के चार राज्यों में यह परियोजना चलाई जा रही है। रीच छत्तीसगढ़ में राज्य टी.बी. कार्यक्रम के साथ एक भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। रीच ने टी.बी. रोग से लड़ कर इससे मुक्त होने वाले टी.बी. चैम्पियंस का एक नेटवर्क बनाया है। एलाइस परियोजना के तहत 904 टी.बी. चैम्पियंस को प्रशिक्षित किया गया है जो सरकार के साथ मिलकर टी.बी. उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हम सभी को मिलकर इस परियोजना के उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि केन्द्र व राज्य शासन इस बीमारी को देश में जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इसके लिए जनजागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पहल पर चलाए जा रहे प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र बनें और एक या एक से अधिक टी.बी. मरीजों को गोद लेकर उन्हें पोषण आहार या अन्य सहायता प्रदान कर सकते हैं।

दीपक बैज के बयान पर किरण सिंहदेव का पलटवार

कहा- जिसकी जैसी क्षमता, वैसी दी जा रही जिम्मेदारी

रायपुर। पीसीसी चीफ दीपक बैज के कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की भाजपा में इज्जत नहीं वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी का सम्मान करती है। जिसकी जैसी क्षमता है, उसे वैसी जिम्मेदारी दी जा रही है। दीपक बैज को हर जगह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में कोई जा नहीं रहा है। भाजपा पूरे विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपती है।

भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेशभर के मोर्चा पदाधिकारियों की प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की आहुत बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के सहयोगी दल को लेकर कहा कि कांग्रेस के लिए कोई नई बात तो नहीं है। कांग्रेस हमेशा उन लोगों के साथ होती है, जो अलग-अलग गतिविधियों में रहते है। इसके बारे में हम सभी जानते है। जम्मू-कश्मीर में सभी प्रतिबंध इन्होंने ने ही तो लगवाया था। भाजपा हमेशा से कहा है कि जम्मू-कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है। कांग्रेस विभाजनकारी शक्तिओं के साथ रहती है, और इसे जनता निश्चित रूप से समझती है।

सदस्यता अभियान पर हो रही बैठक पर किरण सिंहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संयुक्त रूप से सभी मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए है। साथ ही कल प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई गई है। इस तरीके से भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मोर्चा से लेकर बूथ तक सदस्यता अभियान के महापर्व में अपनी सहभागिता तय करेगा।

उन्होंने कहा कि आज की बैठक में जो भी तय होगा संपूर्ण रूप से ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे मोर्चों का स्वरूप विभिन्न रूप से है। इस तरह कुल सात मोर्चे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। बैठक में पवन साय, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अलावा सदस्यता अभियान संयोजक अनुराग सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सदस्यता अभियान में निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचने और सफल बनाने के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग

गृहमंत्री निवास के बाहर पहुंचे हजारों कैंडिडेट्स

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार अभ्यर्थी गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट कर रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। इनके हाथों में तख्ती है, जिसमें इन्होंने जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की है।

गृहमंत्री के बंगले के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी हाथों में तख्ती लेकर बैठे हुए हैं। इन तख्ती पर इन्होंने लिखा है, जल्द रिजल्ट घोषित करें या इच्छा मृत्यु दें। वहीं प्रदर्शकारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गृहमंत्री के बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही अतिरिक्त बल बुलाया गया है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन को आधे घंटे का समय दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी गृहमंत्री के बंगले के अंदर पहुंच गए। ये सभी अभ्यार्थी उनसे मुलाकात की जिद कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और उनके साथ कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अभी अपने बंगले में नहीं हैं।

साल 2018 में छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा की वैकेंसी भाजपा शासन काल में निकाली गई थी। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। 5 साल बीत गए। एक बार फिर भाजपा सरकार आ गई। हालांकि एसआई रिजल्ट की घोषणा अब तक नहीं हुई। साल 2023 में ये परीक्षा हुई है। 8 माह बीत जाने के बाद भी रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है। 1300 से अधिक स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी थी। रिजल्ट घोषणा को लेकर फरवरी माह में भी अभ्यर्थियों ने रायपुर में कैंडल मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया था।

मंकी पॉक्स (एम-पॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु एडवायजरी जारी

- **स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अधिकारियों को शिविर लगाकर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने किया निर्देशित**

रायपुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को मंकी पॉक्स (एम-पॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु जारी एडवायजरी में दिए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरपूर्वक पालन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 20 अगस्त 2024 को मंकी पॉक्स (एमपॉक्स) नामक बीमारी के बचाव व रोकथाम हेतु एडवायजरी जारी की गई है। मंकी पॉक्स (एम पॉक्स) को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 14 अगस्त 2024 को पब्लिक हेल्थ एमरजेन्सी ऑफ इंटरनेशनल कान्स (पीएचईआईसी) को घोषित किया गया है। विभिन्न देशों में संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्वेलेंस, जांच एवमं उपचार हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी मंकी-पॉक्स प्रकरणों की सर्वेलेंस, त्वरित पहचान, जांच एवं उपचार हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

मंकी-पॉक्स एक जीनेटिक बीमारी है जो मुख्य रुप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रों में होता है, परन्तु वर्तमान परिदृश्य में कुछ अन्य देशों में प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं तथा भारत के केरल राज्य में मार्च 2024 में प्रकरण प्राप्त हुए हैं। मंकी-पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति में सामान्यतः बुखार, चकत्ते एवं लिम्फ नोड्स में सूजन पायी जाती है। मंकी-पॉक्स एक स्व-सीमित (सेल्फ-लिमिटेड) संक्रमण है, जिसके लक्षण सामान्यतः 2-4 सप्ताह में समाप्त हो जाते हैं। मंकी-पॉक्स संक्रमण के गंभीर प्रकरण सामान्यतः बच्चों

में पाए जाते हैं। जटिलताओं एवं गंभीर प्रकरणों में मृत्यु दर 1 से 10 प्रतिशत है। मंकी-पॉक्स संक्रमण होने एवं लक्षण उत्पन्न होने का इनक्यूबेशन पीरियड सामान्यतः 6-13 दिन का होता है, परन्तु यह 5 से 25 दिवस तक हो सकता है। मंकी-पॉक्स का संक्रमण त्वचा में चकत्ते आने के 1-2 दिवस पूर्व से लेकर सभी चकत्तों से पपड़ी के गिरने/समाप्त होने तक मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में फैल सकता है।

मंकी-पॉक्स वायरस का संक्रमण पशु से मनुष्य में एवं मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है। मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण मुख्य रूप से लार्ज रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से लम्बे समय तक संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहने से होता है। वायरस का संक्रमण शरीर के तरल पदार्थ घाव के सीधे संपर्क में आने से अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क जैसे दूषित कपड़ों, लिनेन इत्यादि के उपयोग से फैल सकता है। पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण का प्रसार गांव के सीधे संपर्क में आने से हो सकता है। मंकी पॉक्स संभावित प्रकरणों के सर्वेलेंस हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार मंकी पॉक्स के संभावित प्रकरणों का सर्विलांस कर त्वरित पहचान जांच एवं उपचार किए जाने हेतु प्रकरण को आइसोलेट कर संक्रमण का प्रसार रोका जाना, मरीज को उपचार दिया जाना, मरीज के संपर्क व्यक्तियों की पहचान किया जाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को संक्रमण से बचाव हेतु आगाह किया जाना एवं संक्रमण के नियंत्रण और प्रसार को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है।

मंकी-पॉक्स सर्वेलेंस हेतु इस दिशा-निर्देश में दिए मानक-परिभाषाओं का उपयोग किया जाना, प्रत्येक संभावित प्रकरण की सूचना जिला सर्वेलेंस इकाई/राज्य सर्वेलेंस इकाई में अनिवार्य रूप से दिया जाना आवश्यक होगा। इसके एक भी पुष्टिकृत प्रकरण को माना जाए एवं जिला स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा तत्काल विस्तृत आउटब्रेक इनवेस्टिगेशन कर प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। मंकी-पॉक्स के संभावित प्रकरणों की जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सैंपल संग्रहण कर जांच हेतु चिन्हांकित लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। मंकी-पॉक्स के प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सभी संपर्क व्यक्ति की पहचान करने हेतु सभी जिलों में जिला सर्वेलेंस अधिकारी के अधीन कांटेक्ट ट्रेसिंग दल का गठन किया जाएगा। संपर्क व्यक्ति को मंकी-पॉक्स मरीज के संपर्क में आने के 21 दिवस तक बुखार या त्वचा में चकत्ते हेतु दैनिक मॉनिटरिंग किया जाएगा।

सम्पूर्ण बदले माहौल में जम्मू-कश्मीर चुनाव

अवधेश कुमार

जम्मू -कश्मीर विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण निश्चित हो चुके हैं। भाजपा ज्यादातर सीटों पर अकेले लड़ रही है तो कांग्रेस और नैशनल कांफ्रेंस के बीच 85 सीटों पर समझौता हो चुका है। महबूबा मुफ्ती की पी.डी.पी. अकेले मैदान में है। भाजपा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जारी हंगामा चिंता का कारण होना चाहिए। लेकिन जम्मू-कश्मीर का वर्तमान विधानसभा चुनाव केवल दलीय राजनीति तक सीमित नहीं है। पड़ोसी पाकिस्तान तथा चीन के साथ अनेक देशों और उनमें सक्रिय कई संगठन नहीं चाहेंगे कि जम्मू-कश्मीर में भारत निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सफल चुनाव संचालन कर पाए। जम्मू क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवादी घटनाएं इसका प्रमाण हैं कि हमारा पड़ोसी लोकसभा चुनाव के पूर्व से ही परेशान है। लोकसभा चुनाव में भारी मतदान इस बात का प्रमाण था कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लोगों में सुरक्षा को लेकर भय काफी हद तक खत्म हुआ है। उम्मीद है विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति कायम रहेगी। विधानसभा चुनाव की तस्वीर इससे अलग नहीं होगी। कुल सीटें 90 हैं, जिनमें जम्मू की 37 से 43 तथा कश्मीर की 46 से 47 हो चुकी हैं। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीटें आरक्षित हुई हैं तथा 5 का नामांकन किया जाएगा। तो विधानसभा के अंकगणित और संरचना की दृष्टि से यह बहुत बड़ा बदलाव है। बदले हुए वातावरण और सुरक्षा की वर्तमान स्थिति में अब देश विरोधियों के लिए पूर्व चुनावों की तरह बाधित करना या लोगों को डराकर घर में सिमटा देना संभव नहीं। पिछले 5 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में हुए आमूल बदलाव और उसके प्रभाव कम महत्व के नहीं हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि लाल चौक पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इतने शानदार और खुले कार्यक्रम होंगे। यह भी कल्पना करना मुश्किल था कि विद्यालय समय से खुलेंगे, बंद होंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि लंबे समय से पैदा किया गया मजहब के नाम पर अलगाववाद या भारत से नफरत और विरोध का भाव पूरी तरह खत्म हो गया है। किंतु बदले माहौल में इनके लिए संगठित होकर पहले की तरह काम करना संभव नहीं है। सबके परिवार हैं, बच्चों का भविष्य है और बदले वातावरण तथा आर्थिक विकास, सुविधाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के नीचे पहुंचने का लाभ उन्हें भी मिल रहा है। इसमें आम लोग सोचते हैं कि हम इसे क्यों गंवाएं। जिन्होंने सरकारें चलाईं और जिनकी नीतियों से अलगाववाद-आतंकवाद- हिंसा बढ़ी, लोगों को घरों में दुबकना पड़ा, गैर मुसलमानों को घाटी छोड़कर बाहर जाना पड़ा, वे भी आज लोकतंत्र और जन अधिकारों की बात करने लगे हैं। अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार कानून लागू ही नहीं था। क्या मानवाधिकार की बात करने वाले इसकी चर्चा करते हैं? सूचना का अधिकार और बच्चों के शिक्षा का अधिकार कानून भी वहां लागू नहीं था। चुनाव इन सबके प्रभावों से अछूते रहें यह संभव नहीं। पूरे प्रदेश में खासकर घाटी में छोटी-बड़ी नई पार्टियों और नए नेताओं का उभरना इसी बदले राजनीतिक वातावरण और आधारभूमि की परिणति है। यह अलग बात है कि अभी भी लंबे समय से स्थापित पार्टियों, जैसे नैकां का आधिपत्य दिखता है और खिसकते जनाधार के बावजूद पी.डी.पी. की भी कुछ जगह है। कारण, उनके पास राजनीति करने के व्यापक संसाधन हैं, जो दूसरों को उपलब्ध नहीं हैं। नैशनल कांफ्रेंस, पी.डी.पी. सहित कश्मीर की ज्यादातर प्रमुख पार्टियां जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का लगातार विरोध करती रही हैं और लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा था। इस चुनाव में नैशनल कांफ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में 1953 के पूर्व की स्थिति लाएगी। 370 और 35ए की वापसी की बात तो है ही। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी यही घोषणा की है। नैशनल कांफ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में शंकराचार्य पर्वत को तख्त-ए-सुलिमान' और हरि पर्वत 'कोह-ए-मारन' कहा है। यह कट्टर मजहबी मानसिकता का परिचायक है, जो कश्मीर के लोगों का मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया है। यह महबूबा मुफ्ती का पुराना एजेंडा है। कांग्रेस ने नैशनल कांफ्रेंस के साथ समझौता किया है तो उससे पूछा ही जाएगा कि इन पर उसका स्टैंड क्या है। धारा 370 हटाने के बाद कांग्रेस का घोषित स्टैंड यही था कि सत्ता में आने के बाद वह इसे फिर से बहाल करेगी।

जम्मू-कश्मीर चुनाव से नये दौर की उम्मीद

ललित गर्ग

जम्मू एवं कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा निश्चित ही लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती देने के साथ क्षेत्र के लिए विकास के नए दौर के द्वार खोलने का माध्यम बनेगी। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 43 जम्मू और 47 कश्मीर की सीटें हैं, इन चुनावों में जम्मू-कश्मीर के लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर और बड़ी संख्या में मतदान कर ऐसी सरकार बनाये जो शांति और विकास के नये द्वार उद्घाटित करते हुए युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करे एवं आतंकमुक्ति का एक नया अध्याय रचे। आज सबकी आंखें एवं कान चुनावी सरगर्मियों एवं भविष्य के गर्भ में ईवीएम से निकलने वाले जनादेश पर लगी हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है। इस बार के चुनाव अब तक हुए चुनावों से अलग है और खास है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामाकंन भरने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन तमाम बड़ी पार्टियों के बीच असमंजस और अनिश्चितता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कुछ हद तक इस तरह की अनिश्चितता हर चुनाव में होती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के मामले में हालात सामान्य से ज्यादा जटिल हैं और इस असमंजस के पीछे उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी खेमे में माने जाने वाले राज्य के तीनों प्रमुख दलों में सहयोग और संघर्ष दोनों का दिलचस्प घालमेल दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सभी 90 सीटों पर गठबंधन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आलम यह है कि पहले चरण की 24 सीटों का भी बंटवारा मुश्किल साबित हो रहा। पीडीपी इस गठबंधन से बाहर है। फिर भी मुद्दों की एकरूपता के चलते न सिर्फ उमर अब्दुल्ला उससे अपनी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी न खड़ा करने को कह रहे हैं बल्कि खुद महबूबा भी कह चुकी हैं कि अगर उनके अजेंडे को स्वीकार किया गया तो गठबंधन का समर्थन करेंगी। भाजपा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन में नहीं है, इसलिए वहां इस तरह की गफलत नहीं है, लेकिन निर्णय लेना और उसे लागू करना वहां भी जटिल बना हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में दस वर्ष बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर उसे जिस तरह वापस लेना पड़ा, उससे उसकी छिछालेदार तो हुई ही है, अनुशासित दल की उसकी छवि को धक्का भी लगा। स्थिति यह है कि पार्टी ने सोमवार को 44 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के थोड़ी ही देर बाद व्यापक विरोध के कारण उसे वापस ले लिया। इसके बाद जो सूची जारी की गई, उसमें 15 ही प्रत्याशियों के नाम थे। यह आलम तब है, जब पहली सूची भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंजूर की गई थी।

यदि भाजपा औरों से अलग तथा अनुशासित दल की अपनी छवि के प्रति सचेत है तो उसे प्रत्याशी चयन की अपनी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक आकार देना ही होगा। पहले जारी सूची का विरोध जिन कारणों से हुआ, उनमें एक तो दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रत्याशी बनाना रहा और दूसरे दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों का नाम न होना। लगता है भाजपा को अभी भी लोकसभा चुनावों में हुई गलतियों का आभास नहीं है। लोकसभा चुनाव में उसे दूसरे दलों के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का किस तरह नुकसान उठाना पड़ा था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए जारी प्रत्याशियों की सूची का विरोध यह भी बताता है कि भाजपा प्रत्याशी चयन की कोई नीर-क्षीर, पारदर्शी और ऐसी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकी है, जिससे असंतोष, विरोध और भितरघात का सामना न करना पड़े। वैसे यह समस्या केवल भाजपा की ही नहीं, सभी दलों की है। कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को महत्व दें। यह कठिन कार्य नहीं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र विकसित करने से बच रहे हैं।

चुनाव अभियान प्रारम्भ हो रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं। सब राजनैतिक दल अपने-अपने 'घोषणा-पत्र' को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बताकर सब समस्याएं मिटा देने तथा सब रोगों की दवा बन जाने की नैतिकता की बातें करते हुए व्यवहार में अनैतिकता को छिपायेंगे। टुकड़े-टुकड़े बिखरे कुछ दल फेवीकॉल लगाकर एक होंगे। सत्ता तक पहुँचने के लिए कुछ दल परिवर्तन को आकर्षण व आवश्यकता बतायेंगे। इस बार दलों में जितना अन्दर-बाहर होता हुआ दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव परिणामों के बाद भी एक बड़ा दौर असमंजस का चलेगा। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे। इसलिये प्रांत के लोगों को मतदान करते हुए विवेक का परिचय देना होगा।

इन चुनावों की जटिलता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि एक दशक पहले यानी 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के समय अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे से लैस जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य के दर्जे से भी वंचित है। उस चुनाव में दो सबसे बड़ी और मिलकर सरकार बनाने वाली पार्टियां पीडीपी और भाजपा एक-दूसरे की धुर विरोधी हो चुकी हैं। राज्य में अब भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिन्दू बहुल सीटों और कश्मीरी पंडितों के वोट बैंक को अपने खाते में डालने के इरादे से मैदान में उतर रही है और ऐसे में कांग्रेस की हालत खराब होना तय माना जा रहा है। भले ही सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा के साथ गठबंधन करने से इंकार कर दिया है, लेकिन भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए भविष्य में क्षेत्रीय दलों के भाजपा के साथ बहती हवा में जाने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर एक राज्य के रूप में शुरू से विशिष्ट रहा है, इस दृष्टि से वहां होने वाले चुनाव भी विशेष एवं अन्य राज्यों से भिन्न है। बड़ी बात यह है कि पार्टियां एक-दूसरे के बारे में चाहे जो भी कहें, ये सभी भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव में हिस्सेदारी कर रही हैं और जनादेश को भी स्वीकार करेंगी। निश्चित ही इन चुनाव परिणामों से उम्मीद जगी है कि यहां से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक विकास और शांति-समृद्धि-स्थिरता का नया दौर शुरू होगा। ऐसा होना ही इन चुनावों की सार्थकता है।

जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेगी। मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड लाख पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। चुनाव घोषित हो जाने से तथा प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से जो क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसने ही सबके दिमागों में सोच की एक तेजी ला दी है। प्रत्याशियों के चयन व मतदाताओं को रिझाने के कार्य में तेजी आती जायेगी। परम आवश्यक है कि सर्वप्रथम राज्य का वातावरण चुनावों के अनुकूल बने। राज्य ने साम्प्रदायिकता, आतंकवाद तथा अस्थिरता के जंगल में एक लम्बा सफर तय किया है। उसकी मानसिकता घायल है तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। पुराने चेहरों पर उसका विश्वास नहीं रहा। अब प्रत्याशियों का चयन कुछ उसूलों के आधार पर होना चाहिए न कि जाति और जीतने की निश्चितता के आधार पर। मतदाता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ की परिपक्वता दिखाई दे रही है। ये चुनाव ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब राज्य लम्बे दौर की विभिन्न चुनौतियों से जूझने के बाद शांति एवं विकास की राह पर अग्रसर है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

प्रक्षिप्त-पाठ (भाग-6)

गतांक से आगे...

(2) साम्प्रदायिक प्रक्षिप्त- वेदादि ग्रन्थों में एक ही परमात्मा की उपासना के लिये मनुष्य- प्रकृति के मुख्य पाँच विभागों के विचार से वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गाणपत्य नामक पाँच सम्प्रदायों का निर्देश मिलता है। आरम्भ में प्रत्येक अधिकारी के लिये किसी एक ही रूप के आश्रय से अनन्यताभाव की भी एक सीमा तक श्रावश्यकता प्रकट की गई है, अन्त में यही अनन्यता-भाव एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म के रूप में परिणत हो जाता है, इस वैज्ञानिक उपासना पद्धति का विवेचन उक्त ग्रंथ में यथास्थान किया जायगा ।

यहाँ केवल इतना समझ लेत्ता चाहिये कि पुराणों में भी उक्त वैदिक सिद्धान्त का पर्याप्त पोषण किया गया है। तदनुसार प्रत्येक पुराण में यथासम्भव पाँचों सम्प्रदायों के वर्णन के साथ 2 किसी एक सम्प्रदाय को विशिष्ट स्थान दिया है। इस सीमा तक वर्णित साम्प्रदायिकता को हम प्रक्षिप्त मानने के लिये प्रस्तुत नहीं। जो शब्द आधुनिक समालोचकों से- जिसका विवाह उसके गीप्त वाली लोकोक्ति के अनुसार प्रत्येक पुराण अपने 2 वर्णित ग्रन्थ-नायक को सब कुछ मानकर बाकियों को उसके अनुचर सिद्ध करता है।- ऐसे उद्गार प्रकट करवाते हैं, वही शब्द सम्प्रदाय समन्वय के तत्त्वज्ञों को अधिकारी भेद से सुव्यव-स्थित एवं अनन्यता प्रतिपादक प्रतीत होते हैं, इसमें केवल संकुचित और व्यापक दृष्टि का ही अन्तर है। अत: हम पाश्चात्य समालोचकों और उनके पिछलगुवे भारतीयों की दृष्टि में प्रक्षिप्त जंचने वाले प्रदर्शित सोमा के अन्तर्वर्ती साम्प्रदायिक अंशों को प्रक्षिप्ताभास नाम से स्मरण करेंगे।

यथा- नास्ति विष्णो: परं धाम (पद्म 6 । 31 । 306) योगमायावशे सर्वम (दे0 भा0 5।18।34) नास्ति शर्वसमो देव: (म0 भारत अनु0 15।11) आदि श्लोक एकेश्वरवाद में ही परिणत हो जाते हैं ।

क्रमश: ...

हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद

योगेश कुमार गोयल

प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत में हॉकी के पूर्व कप्तान मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को 'खेल दिवस' के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को जन्मे ध्यानचंद हॉकी के ऐसे महान् खिलाड़ी और देशभक्त थे कि उनके करिश्माई खेल से प्रभावित होकर जब एक बार जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें अपने देश जर्मनी की ओर से खेलने का न्यौता दिया तो ध्यानचंद ने उसे विनम्रतापूर्वक ठुकराकर सदा अपने देश के लिए खेलने का प्रण लिया। हालांकि उन्हें बचपन में खेलने का कोई शौक नहीं था और साधारण शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे सोलह साल की आयु में दिल्ली में सेना की प्रथम ब्राह्मण रेजीमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। सेना में भर्ती होने तक उनके दिल में हॉकी के प्रति कोई लगाव नहीं था। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया हॉकी खिलाड़ी सूबेदार मेजर तिवारी ने, जिनकी देखरेख में ही ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और बहुत थोड़े समय में ही हॉकी के ऐसे खिलाड़ी बन गए कि उनकी हॉकी स्टिक मैदान में दनादन गोल दागने लगी। उनकी हॉकी स्टिक से गेंद अक्सर इस कदर चिपकी रहती थी कि विरोधी टीम के खिलाड़ियों को लगता था, जैसे ध्यानचंद किसी जादुई हॉकी स्टिक से खेल रहे हैं। इसी शक के आधार पर एक बार हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर भी देखी गई कि कहीं उसमें कोई चुम्बक या गोंद तो नहीं लगा है लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। उन्हें अपने जमाने का हॉकी का

सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, जिसमें गोल करने की कमाल की क्षमता थी। भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया गया था।

1922 में सेना में भर्ती होने के बाद से 1926 तक ध्यानचंद ने केवल आर्मी हॉकी और रेजीमेंट गेम्स खेले। उसके बाद उन्हें भारतीय सेना टीम के लिए चुना गया, जिसे न्यूजीलैंड में जाकर खेलना था। उस दौरान हुए कुल 21 मैचों में से उनकी टीम ने 18 मैच जीते जबकि दो मैच ड्रा हुए और केवल एक मैच उनकी टीम हारी। मैचों में ध्यानचंद के सराहनीय प्रदर्शन के कारण भारत लौटते ही उन्हें लांस नायक बना दिया गया और उन्हें सेना की हॉकी टीम में स्थायी जगह मिल गई। 1928 में एम्सटर्डम में होने वाले ओलम्पिक के लिए भारतीय टीम का चयन करने हेतु भारतीय हॉकी फेडरेशन द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल पांच टीमों ने हिस्सा लिया। ध्यानचंद को सेना द्वारा यूनाइटेड प्रोविंस की ओर से टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति मिल गई और अपने शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें ओलम्पिक में हिस्सा लेने वाली टीम में जगह मिल गई। 1928, 1932 और 1936 के ओलम्पिक खेलों में ध्यानचंद ने न केवल भारत का नेतृत्व किया बल्कि लगातार तीनों ओलम्पिक में भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाए। दो बार के ओलम्पिक चैम्पियन केशव दत्त का ध्यानचंद के बारे में कहना था कि वह हॉकी के मैदान को उस ढ़ंग से देख सकते थे, जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है।

अमरीकी सैन्य उद्योग को युद्ध से मुनाफा

संथोश मैथ्यू

युद्ध निस्संदेह अपार विनाश और पीड़ा लाते हैं, मगर उन्होंने कुछ अमरीकी संस्थाओं के लिए पर्याप्त लाभ भी उत्पन्न किया है, जो संघर्ष और आर्थिक लाभ के एक चक्र को बढ़ावा देता है। अमरीकी सैन्य-औद्योगिक परिसर (द अमेरिकन मिलिट्री-इंडस्ट्रीयल काम्पलैक्स) की जड़ों का पिछले द्वितीय विश्व युद्ध में पता लगाया जा सकता है। युद्ध के प्रयास के लिए संसाधनों की बड़े पैमाने पर लामबंदी ने अमरीका को एक प्रमुख सैन्य शक्ति में बदल दिया, जिसमें एक मजबूत रक्षा उद्योग वैश्विक संघर्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उभरा। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, और जनरल डायनामिक्स जैसी कंपनियां युद्ध के प्रयास की अभिन्न अंग हो गईं, एक अभूतपूर्व पैमाने पर विमानों, जहाजों और हथियारों का उत्पादन करते हुए।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू-राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। अमरीका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध ने सैन्य तत्परता की एक स्थायी स्थिति की आवश्यकता पैदा कर दी, जिससे रक्षा में निरंतर सरकारी निवेश हुआ। इस अवधि में एक स्थायी हथियार उद्योग की स्थापना और रक्षा ठेकेदारों के प्रसार को देखा गया, जो अमरीकी अर्थव्यवस्था और राजनीति में सैन्य-औद्योगिक परिसर को आगे बढ़ाता है। यू.एस. वैश्विक जिम्मेदारियों और हितों के साथ एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसे अक्सर साम्यवाद को काबू करने की आवश्यकता से उचित ठहराया गया। इस नई भूमिका में दुनिया भर में सैन्य ठिकानों को बनाए रखने और विस्तार करने की आवश्यकता थी, जो तैयारियों की निरंतर स्थिति को सुनिश्चित करता है।

कोरियाई युद्ध (1950-1953) शीत युद्ध के युग

के पहले महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक था, जहां अमरीका एशिया में साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सैन्य रूप से लगा हुआ था। इस युद्ध ने एक पैटर्न की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां सैन्य संघर्षों, जो अक्सर वैचारिक लड़ाई की आड़ में शुरू किए गए, ने रक्षा उद्योग को बढ़ाने में मदद की। वियतनाम युद्ध (1955-1975) ने इसे और अधिक बढ़ावा दिया, क्योंकि यह अमरीकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला और विवादास्पद संघर्षों में से एक बन गया। युद्ध ने रक्षा ठेकेदारों के लिए लेकिन अत्यंत मानवीय पीड़ा और घरेलू उथल-पुथल की कीमत पर विशाल लाभ उत्पन्न किया।

शीत युद्ध का युग : निरंतर संघर्ष और मुनाफाखोरी। शीत युद्ध के दौरान अमरीका ने लैटिन अमेरिका से मध्य-पूर्व तक कई प्रॉक्सी युद्धों और सैन्य हस्तक्षेपों में भाग लिया। क्यूबा मिसाइल संकट, द बे ऑफ पिग्स आक्रमण और दुनिया भर में कम्युनिस्ट विरोधी शासन के लिए समर्थन ने सोवियत प्रभाव से निपटने के लिए अमरीका की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। प्रत्येक संघर्ष ने हथियार प्रौद्योगिकी में बढ़े हुए सैन्य खर्च और नवाचार के लिए एक बहाना प्रदान किया, जिससे रक्षा उद्योग के लिए निरंतर मुनाफा सुनिश्चित हुआ। इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक हथियारों के लिए दौड़ थी, जिसकी विशेषता परमाणु हथियारों का तेजी से विकास और भंडार थी। इस अवधि में मिसाइल प्रौद्योगिकी, स्टैल्थ विमान और अन्य परिष्कृत हथियारों में प्रगति भी देखी गई, सभी अमरीकी करदाताओं द्वारा वित्त पोषित। शीत युद्ध के अंत ने सैन्य-औद्योगिक परिसर के प्रभाव को कम नहीं किया। इसकी बजाय, नए खतरे सामने आए और परिसर तदनुसार अनुकूलित हो गया।

खाड़ी युद्ध (1990-1991) ने अमरीका के तकनीकी सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया और तेल-समृद्ध मध्य-पूर्व में अपने हितों की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा ठेकेदारों ने युद्ध से पर्याप्त मुनाफा कमाया, सटीक-निर्देशित युद्ध-सामग्री से लेकर उन्नत कॉम्बैट सिस्टम तक सब कुछ की आपूर्ति की। 11 सितंबर, 2001 के हमलों ने आतंक पर युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया, एक लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष, जिसने अमरीकी विदेश नीति पर सैन्य-औद्योगिक परिसर की पकड़ को मजबूत किया। अफगानिस्तान और इराक पर आक्रमणों के परिणामस्वरूप रक्षा खर्च में नाटकीय वृद्धि हुई, जिसमें हॉलिबर्टन और ब्लैकवाटर (अब एकैडमी) जैसी कंपनियों ने पुनर्निर्माण और सुरक्षा सेवाओं के लिए आकर्षक अनुबंध हासिल किए। हाल के वर्षों में, सैन्य-औद्योगिक परिसर मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों, रूस और चीन के साथ बढ़ते तनाव और आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध से प्रेरित है।

अमरीकी रक्षा बजट दुनिया में सबसे बड़ा बना हुआ है, जिसमें अगली पीढ़ी की हथियार प्रणालियों को विकसित करने और सैन्य ठिकानों के एक विशाल नैटवर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन आबंटित किया गया है। अमरीकी समर्थन के साथ, ईरान में इसराईल द्वारा फिलिस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री और हमास के प्रमुख इस्माइल हानेह की हालिया हत्या, सैन्य-औद्योगिक परिसर के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करती है। ये कार्रवाइयां और इस क्षेत्र में बाद के अमरीकी सैन्य बिल्डअप, यह उदाहरण देते हैं कि कैसे भू-राजनीतिक युद्धाभ्यास अक्सर दोहरे उद्देश्यों की सेवा करते हैं-रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना और रक्षा उद्योग के लिए निरंतर लाभ सुनिश्चित करना।

आज का इतिहास

1845 प्रसिद्ध पत्रिका साइंटेफिक अमरीकन का पहला संस्करण छपा।
1845 वैज्ञानिक अमेरिकी पत्रिका ने अपनी पहली प्रति प्रकाशित की।
1861 अमेरिकी गृहयुद्ध-संघ की सेना ने उत्तरी कैरोलिना के बाहरी बैंकों पर दो संघिधत किलों पर कब्जा करके सफलतापूर्वक अपनी रणनीति को बढ़ाया।
1864 पहला जिनेवा कन्वेंशन 26 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित युद्ध के नियमों को नियंत्रित करता।
1867 संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में मिडवे द्वीप पर कब्जा किया।
1901 डुमगेटे में सिलिमन विश्वविद्यालय, नीग्रोस ओरिएंटल, फिलीपींस, देश में स्थापित होने वाला पहला अमेरिकी निजी स्कूल बन गया।
1901 अमेरिका के पहले निजी स्कूल, सिलीमान विश्वविद्यालय की स्थापना फिलीपींस में की गयी।
1903 रूसी युद्धपोत स्लाव, पांच बोरोडिनो-वर्ग युद्धपोतों में से आखिरी, लॉन्च किया गया था।
1909 दिमित्रियोसालिस की सरकार के खिलाफ एक सैन्य तख्तापलट डीएटैट ग्रीस के एथेंस के गौडी इलाके में शुरू हुआ।
1911 याही के अंतिम सदस्य, जिसे इशी के रूप में जाना जाता है, यूरोपीय अमेरिकियों से जुड़ने के लिए ओरोविले, कैलिफोर्निया के पास जंगल में उभरा।
1914 प्रथम विश्व युद्ध के पहले नौसैनिक युद्ध में, ब्रिटिश जहाजों ने उत्तरी सागर के हेलिगोलैंड बाइट क्षेत्र में जर्मन बेड़े को हराया।
1916 प्रथम विश्वयुद्ध में इटली ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
1924 अगस्त विद्रोह के रूप में जाना जाने वाला, जॉर्जियाई सोवियत समाजवादी गणराज्य में सोवियत शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह शुरू हुआ।
1937 जापानी युद्धपोत और हवाई जहाज शंघाई में महिलाओं और बच्चों पर स्कूली बच्चों के साथ बम और स्ट्राफ रेलवे गाड़ी के रूप में युद्ध शुरू कर रहे हैं। पूरी दुनिया ईमानदारी से आपत्ति कर रही है, लेकिन जापानी कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं और हमेशा की तरह निर्मम हो रहे हैं।
1937 टोयोटा मोटर्स, जो अब दुनिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है, स्वतंत्र कंपनी के रूप में टोयोटा इंडस्ट्रीज से अलग हो गई थी।

'कंगना कल्चर' के अपने ही नेताओं से परेशान भाजपा

अजय बोकिल

बीते छह माह में संविधान, आरक्षण, जातिगणना और किसान आंदोलन के मुद्दे भाजपा की ऐसी दुखती रग बन गए हैं कि वो उसे कहां और कैसे राजनीतिक नुकसान पहुंचाएंगे, इसका अंदाजा भाजपा भी ठीक-ठीक नहीं लगा पा रही है। इनमें भी लंबे किसान आंदोलन के चलते तीन विवादित कृषि कानून मोदी सरकार द्वारा वापस ले लिए जाने के बाद यह मामला पिछले कुछ समय से हाशिए पर चला गया था, लेकिन भाजपा सांसद और बड़बोली अभिनेत्री कंगना रनौत ने इन हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले फिर इस मुद्दे को कुरेद कर भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है।

लगता है पार्टी को अब अपने ही नेताओं के ऐसे घर जलाऊ बयानों पर पानी डालने के लिए अलग से फायर ब्रिगेड रखनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी में कंगना जैसे नेता हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। एक समय तक कांग्रेस मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा जैसे बड़बोले नेताओं से परेशान थी। लेकिन अब लगता है यह काम भाजपा में भी कुछ लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। भाजपा की बेबसी यह है कि वह इन मुद्दों पर लगातार नुकसान झेल रही है, लेकिन इसका कोई तोड़ या ठोस जवाब उसके पास नहीं है। यहां तक कि ऐसे नेताओं के खिलाफ वह कोई प्रभावी कार्रवाई भी नहीं कर पाती। इसके पीछे कारण या तो असहायता है या फिर खुद ऐसे लोगों को पार्टी की शह है।

बेशक, राजनीति में बेबाकी भी एक व्यक्तिगत गुण है, लेकिन बेबाकी और अविवेकी होने में बुनियादी फर्क है। अगर बगैर राजनीतिक समझ के कोई सार्वजनिक बयान दिया जाता है तो यह या तो मूर्खता है या फिर उद्दंडता। बिना सोचे समझे सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए कुछ भी कह देना खुद अपने और अपनी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वैसे भी कंगना रनौत ऐसे ही विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो बेहतर अभिनेत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और सामाजिक समझ भी उतनी ही परिपक्व हो, जरूरी नहीं है। वरना कोई कारण नहीं था कि हरियाणा विस चुनाव के ऐन पहले काफी हद तक ठंडे पड़ चुके किसान आंदोलन को बुरे लफ्जों में कोसा जाता। कंगना के बयान के बाद हरियाणा में नाराज किसानों के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि कंगना ने ऐसा बयान तब दिया है कि जब वो इसी मुद्दे पर सीआईएसफ की एक महिला कांस्टेबल के हाथों सरेआम थप्पड़ खा चुकी हैं।

किसान आंदोलन कितना जायज, तार्किक और राजनीति से प्रेरित था, इसके पीछे किन ताकतों का हाथ था, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसे अलगाववादियो और विदेशी हाथों से संचालित होने के आरोप लगाना और वो भी इस समय, राजनीतिक बुद्धिमानी कतई नहीं है। अगर यह साफगोई भी है तो उसमें समझदारी का तत्व गायब है। वैसे भी कंगना न तो स्वयं किसान परिवार से हैं और न ही इस आंदोलन के साथ उनका किसी तरह का कोई सम्बन्ध रहा है। हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा पर हुए किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन स्थल पर लाशें लटकती देखी गईं और बलात्कार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए होते तो

किसानों के विरोध प्रदर्शन से भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। इस बयान ने उन भाजपाइयों को भी चौंका दिया जो, लोकसभा चुनाव में हुई चूकों की राजनीतिक दुरूस्ती में लगे हुए हैं। इस बयान से संभावित सियासी नुकसान को भांपकर भाजपा ने तुरंत खंडन जारी किया कि कंगना का बयान पार्टी की अधिकृत राय नहीं है। उन्हें नीतिगत मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। साथ में कंगना को चेतावनी दी गई कि वो आइंदा ऐसे मुद्दों पर न बोलें। उधर विपक्ष ने इस बयान को तुरंत लपका और भाजपा पर प्रहार शुरू कर दिए।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कंगना का बयान भाजपा की किसान विरोधी नीति का सबूत है। इसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसानों से किए वादे पूरा करने में नाकाम रहा तंत्र किसानों के प्रति दुष्प्रचार में लगा हुआ है। राहुल ने कहा कि भाजपा कंगना के बयान से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करे। उन्होंने यह भी कहा कि तीन विवादित कृषि कानूनो के खिलाफ 378 दिन चले मैराथन संघर्ष में 700 किसानों ने बलिदान दिया।

उन्हें बलात्कारी व विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति व नीयत का परिचायक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का अपमान है। इंडिया गठबंधन किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। कुछ ऐसे ही बयान आम आदमी पार्टी, सपा की तरफ से भी आए। क्योंकि सबको पता है कि किसानो का मुददा हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के लिए कितना संवेदनशील है। इस मामले में कोई भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया भाजपा की जमावट को जड़ से हिला सकती है। दरअसल, ऐसे आत्मघाती बयान या तो अतिआत्मविश्वास की कोख से जन्म लेते हैं या फिर विवेकहीनता का परिणाम होते हैं। इसमे यह उद्दंड भाव छिपा होता है कि जनता उनकी बंधुआ है। वो कुछ भी करें या कहें, सत्ता उन्हीं के हाथ रहनी है। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द् मोदी का 'अबकी बार चार सौ पार का नारा' भी इसी मुगालते का नतीजा था। तीन विधानसभा चुनावों में भाजपा की बंपर जीत और राम मंदिर में भगवान राम की भव्य प्रतिष्ठापना ने ऐसी सियासी धुंध पैदा की कि सत्ताधीशों को शायद सतह के नीचे की खदबदाहट सुनाई देना ही बंद हो गई।

यह राजनीतिक बधिरता ही ऐसे बयानों को प्रेरित करती है, जो अपने घर पर ही 'बुलडोजर चलाने' जैसी साबित होती है। लोकसभा चुनाव के समय भी यही हुआ था। 'चार सौ पार' इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, यह नरेटिव गुप्त गंगा की तरह ऐसा लहराया कि चार सौ पार तो दूर भाजपा बहुमत के आंकड़ों से भी 32 सीट दूर रह गई। इसकी शुरूआत भी किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि 'कंगना कल्चर' के भाजपाई सांसदों अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरूण गोविल आदि ने की थी। कांग्रेस और विपक्ष ने इसी बड़बोलेपन को अपना अचूक हथियार बनाकर भाजपा की नीयत पर ही हमले शुरू कर दिए। डेमेज कंट्रोल के तौर पर भाजपा ने कुछ सांसदों के टिकट भी काटे, लेकिन पार्टी की मंशा पर उठी उंगलियों को वापस मोड़ देने का कोई कारगर इलाज उसके पास नहीं था। जब तक वो इन सवालों का माकूल राजनीतिक जवाब देती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाजपा की परेशानी यह है कि अब राहुल गांधी उसकी दुखती रग बने चारों मुद्दों पर लगातार और बेखौफ हमला किए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को 'पप्पू' अथवा 'अपरिपक्व राजनीतिज्ञ' साबित करने के पुराने फार्मूले काम नहीं आ रहे हैं। बीते दस सालों में यह शायद पहली बार है, जब देश तो क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा अपना एजेंडा सेट करने के बजाए विपक्षी हमलो से बचाव के लिए तलवार पर धार करने में ही उलझी है।

यह बात मोदी सरकार के कोर मुद्दों पर बैकफुट पर जाने और अपने ही नेताओं को कायदे में न रख पाने से जाहिर है। कंगना के ताजा बयान से हरियाणा में भाजपा का कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, यह तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलेगा, लेकिन पार्टी कंगना के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। यह साफ है।

बदले माहौल का नतीजा है कश्मीर में चुनाव

अवधेश कुमार

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव पर निश्चय ही पड़ोसी पाकिस्तान तथा चीन के साथ विश्व के अनेक देशों और उनमें काम करने वाले कई संगठनों और व्यक्तियों की गहरी दृष्टि होगी। पाकिस्तान और चीन दोनों नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भारत निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सफल चुनाव संचालन कर पाए।

जम्मू क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवादी घटनाएं इसका प्रमाण हैं कि हमारा पड़ोसी किस तरह लोकसभा चुनाव के पूर्व से ही परेशान है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने जितनी बड़ी संख्या में मतदान किया, वह इस बात का प्रमाण था कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां लोगों के अंदर सुरक्षा को लेकर भय काफी हद तक खत्म हुआ है और आश्वस्ति का सामूहिक मानस कायम हो चुका है। उम्मीद है विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति कायम रहेगी। लोकसभा चुनाव के बारे में भी यही कहा गया कि यह अभी तक का सबसे सफल, शांत और सर्वाधिक मतदाताओं की भागीदारी वाला चुनाव साबित हुआ। विधानसभा चुनाव की तस्वीर इससे अलग नहीं होगी। प्रदेश में लंबे समय से रुका परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। इसमें जम्मू की सीटों को 37 से 43 तथा कश्मीर की सीटों को 46 से 47 किया जा चुका है। इस तरह 90 सीटें हैं। पहली बार वहां अनुसूचित जनजाति के लिए सात सीटें आरक्षित हुई हैं तथा पांच का नामांकन किया जाएगा। तो विधानसभा के अंकगणित और संरचना की दृष्टि से यह बहुत बड़ा बदलाव है। भारत विरोधी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति से परेशान हैं। किंतु बदले हुए वातावरण और सुरक्षा की वर्तमान स्थिति में अब उनके लिए पहले के चुनावों की तरह इसे बाधित करना या लोगों को डराकर घर में सिमटा देना संभव नहीं है। इस चुनाव में किस पार्टी की क्या हैसियत रहेगी, राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्व है किंतु इसके साथ पिछले 5 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में हुए आमूल बदलाव और उसके प्रभाव भी कम महत्व के नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर जैसे लंबे समय तक असामान्य और अशांत रहे प्रदेश के पूरे वातावरण को पटरी पर लाने की कल्पना भी देश में नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी लाल चौक पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इतने शानदार और खुले कार्यक्रम होंगे। यह भी कल्पना मुश्किल था कि पूरे प्रदेश के विद्यालय समय से खुलेंगे, बंद होंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि लंबे समय से पैदा किया गया अलगाववाद या भारत से नफरत और विरोध का भाव वहां पूरी तरह खत्म हो गया है। किंतु बदले हुए माहौल में इन सबके लिए संगठित होकर पहले की तरह काम करना संभव नहीं है।

लेटरल एंट्री की राजनीति : सिर्फ कोटा से उत्कृष्टता नहीं मिलेगी

पूनम आई. कौशिश

आरक्षण राशन तमाशा फिर से राजनीतिक थाली में परोस दिया गया है क्योंकि हमारे नेता अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए लोकलुभावन हो-हल्ला मचाना जारी रखते हैं, जो नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) की एक बड़ी चुनौती बन गया और राजनीतिक तू-तू मैं-मैं का शिकार हो गया। कोटा के चश्मे के माध्यम से राजनीतिक लड़ाई में अच्छी नीतियों के नुकसान होने का एक क्लासिक मामला। प्रासंगिक रूप से, यू.पी.एस.सी. ने 18 अगस्त को अनुबंध के आधार पर या प्रतिनियुक्ति के जरिए पार्श्व प्रवेश के माध्यम से 24 केंद्रीय मंत्रालयों में कई भूमिकाओं के लिए 45 पदों का विज्ञापन दिया। इनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पद शामिल थे। जाहिर तौर पर इसने विपक्ष के साथ-साथ भाजपा के सहयोगियों (जद (यू), लोजपा) को भी परेशान किया, जिनका कहना था कि भाजपा को आरक्षण के मुद्दे ने काफी नुकसान पहुंचाया, जैसा कि हालिया लोकसभा चुनावों में स्पष्ट हुआ।

इससे पार्टी को अहसास हो गया कि आरक्षण अपने आप में चुनावी दृष्टि से अति संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए उसने अपना रुख बदल लिया। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस के राहुल गांधी आरक्षण को छोटा करने और सरकारी नौकरियों में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. आरक्षण को छीनने के लिए एक 'राष्ट्र-विरोधी कदम' के रूप में लेटरल एंट्री की आलोचना कर रहे हैं, तो वह यह आसानी से भूल गए कि उनकी यू.पी.ए. सरकार ने ही लेटरल एंट्री की अवधारणा विकसित की थी और 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) स्थापित किया था। वास्तव में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो 'बाहरी विशेषज्ञ' थे। इसी तरह इंफोसिस के पूर्व प्रमुख नंदन नीलेकणि भी हैं, जिन्होंने आधार की अगुवाई की। इसके अलावा, सिंह के कार्यकाल के दौरान ऊर्जा मंत्रालय ने नामांकन के आधार पर एक प्रमुख औद्योगिक घराने की पृष्ठभूमि वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया।

छठे वेतन आयोग 2013, नीति आयोग 2017 ने भी इसे दोहराया, जिसमें मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर अधिकारियों को 3 साल के अनुबंध पर शामिल करने का समर्थन किया गया,

जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता था, जो तब तक केवल आई.ए.एस. और केंद्रीय सिविल सेवाओं के नौकरशाह ही करते थे। 2019 में 6,077 संयुक्त सचिव आवेदनों में से 9 को 9 मंत्रालयों में नियुक्त किया गया, इसके बाद 2021, 2023 में तीन दौर की नियुक्ति की गई। हाल ही में, सरकार ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 वर्षों में 63 लेटरल एंट्री नियुक्तियां की गई हैं। वर्तमान में, 57 लेटरल एंट्री केंद्रीय मंत्रालयों में तैनात हैं।

निस्संदेह, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में नए विकासशील क्षेत्रों और हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण सरकारी कार्यकलापों में क्षमताओं को समृद्ध करने के लिए नए विचारों, ऊर्जा और डोमेन विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि शासन के जटिल कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके और वितरण तंत्र को तेज और कुशल बनाया जा सके। साथ ही वांछित परिणामों के लिए सरकार में सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र की संस्कृति को शामिल किया जा सके। अफसोस, समस्या तब होती है जब बौने नेताओं द्वारा संचालित हमारी क्षुद्र राजनीति सामाजिक न्याय और समानता की अनिवार्यताओं के खिलाफ संकीर्ण रूप से परिभाषित आरक्षण शर्तों में 'विशेषज्ञता' और 'योग्यता' को समान मानती है। नतीजतन, कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसे एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के हितों के खिलाफ माना जाएगा।

जैसा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एस.सी., एस.टी. उप-कोटा पर रेखांकित किया है कि योग्यता को समानता और समावेशिता के सामाजिक सामान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि संपन्न और वंचितों या योग्यता और वितरण न्याय के बीच संघर्ष के रूप में। नीतिगत दृष्टि से कोटा पर अत्यधिक जोर शासन को प्रभावित कर सकता है। इससे भी बुरी बात यह है कि नौकरशाह भी सरकार चलाने में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को स्थान देने में अनिच्छुक हैं। सत्ता और भ्रष्टाचार बाबुओं की सनकी नियंत्रण मानसिकता के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। इसके अलावा, लगातार बढ़ते आरक्षण का समर्थन नहीं किया जा सकता। मुझे गलत मत समझिए, निश्चित रूप से सामाजिक न्याय वांछनीय है और समान अवसर और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के सरकार के मौलिक मिशन के साथ-साथ एक प्रशंसनीय लक्ष्य है। फिर भी, गरीबी के दलदल से उन्हें ऊपर उठाने में भारत की 7 दशकों की ऊब यह दर्शाती है कि असंख्य वर्गों, जातियों, उपजातियों और वंचितों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई भी कानून गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं कर पाया है, भले ही कुछ लोगों को नौकरी मिल गई हो।

इसके अलावा यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि कोटा के बाद आरक्षण पाने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोई प्रयास किया जाता है या नहीं। कोटा लोगों के उत्थान के लिए एकमात्र रामबाण उपाय नहीं है। इसके अलावा इस बहाने से प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देना खतरनाक है, कि इससे वंचितों का उत्थान होगा। लेटरल एंट्री सकारात्मक कार्रवाई का साधन नहीं है और कभी नहीं थी। यह विशेषज्ञों के लिए शासन में भाग लेने का एक साधन है जो अन्यथा सरकार में शामिल होने पर विचार नहीं करेंगे।

सच है, लेटरल एंट्रीकर्त्ता प्रणालीगत बीमारियों और कमियों के लिए कोई जादुई इलाज नहीं हैं और अधिक मौलिक पुनर्गठन के लिए एक मामला बनाया जा सकता है जो विशिष्ट अवधि के लिए अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के लिए विशेषज्ञता और विशेषज्ञता के अंतराल को भरने में मदद कर सकता है। यू.एस., यू.के. जैसे विकसित देश नियमित रूप से सरकार के बाहर से विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं। हमारे नेताओं को पहचानने की जरूरत है कि असमानताएं मौजूद हैं और उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। नौकरियों में सिर्फ कोटा होने से उत्कृष्टता नहीं मिलेगी। समय आ गया है कि केंद्र-राज्य सरकारें आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करें और आरक्षण के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकें। अन्यथा हम अक्षमता और सामान्यता के जाल में फंस सकते हैं। आरक्षण पर बार-बार जोर देने से नुकसान हो सकता है और शायद इससे दरारें और बढ़ेंगी।

महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्किोण बदले

कपिल सिब्बल

सभी अपराधों में बलात्कार सबसे जघन्य अपराध है। बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से देश का जनमानस व्यथित है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध की बार-बार होने वाली घटनाएं राष्ट्रीय शर्म का भी विषय हैं। पहले ऐसी घटनाएं बहुत कम दर्ज होती थीं। ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग से यह जागरूकता पैदा हुई है कि इस तरह के जघन्य अपराध की जांच तेजी से की जानी चाहिए और शीघ्र फैसला आना चाहिए। सिर्फ 2016 से 2022 के बीच बच्चों से बलात्कार के मामलों में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2016 में 19,765 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 27,616 था। 2021 में यह संख्या बढ़कर 36,381 हो गई और 2022 में 38,911 थी। अकेले 2021 में भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 49 अपराध दर्ज किए गए। यह संभवत: अधिक रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में जागरूकता के कारण है।

पीड़ितों को न्याय दिलाने में हेल्पलाइन और एजेंसियों के माध्यम से अधिक पहुंच ने भी मदद की है। पीड़ितों के परिवारों के पास अब यह सुनिश्चित करने का रास्ता है कि ऐसे अपराधियों को सजा दिलाई जाए। बलात्कार कई चीजों का लक्षण है। यह हावी होने और अपनी ताकत दिखाने की इच्छा का लक्षण है, जो एक नकारात्मक मानवीय गुण है। उपरोक्त डाटा हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? यह कि समाज कहीं न कहीं स्त्री-द्वेषी है और मानता है कि महिलाएं आनंद और उपहास दोनों की वस्तु हैं। यह मानसिकता हमारे अंतर्निहित सांस्कृतिक परिवेश से उभरती है जिसमें लड़कियों को हमारे परिवारों में दोयम दर्जे का स्थान दिया जाता है। मैं उन प्रबुद्ध परिवारों की बात नहीं कर रहा जो उदार परंपराओं को अपनाते हैं। लेकिन वहां भी, हम कई मौकों पर भेदभाव का तत्व पाते हैं जब उन्हें समाज में एक समान भागीदार के रूप में अपने सपनों को साकार करने की अनुमति देने की बात आती है। बाल विवाह हालांकि अवैध है, फिर भी यह अभी भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है। यही कारण है कि समाज में एक महिला का स्थान एक अनुरक्त पत्नी के रूप में माना जाता है, जो घर की सेवा करती है, न कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में, जिसे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का समान अधिकार है। लड़कियों के बड़े होने पर उनके पास बहुत कम

विकल्प होते हैं, करियर के रास्ते सीमित होते हैं। ज्यादातर मौकों पर शादी ही एकमात्र विकल्प होता है, जहां साथी का चुनाव भी शायद ही कभी संभव हो पाता है।

ग्रामीण इलाकों में जहां खेती-बाड़ी ही परिवार का मुख्य आधार है, महिलाएं घर चलाने के लिए खेतों में काम करती हैं। उनके विकल्प कहीं ज्यादा सीमित हैं। कई प्रतिभाशाली युवा लड़कियां हैं जो अपना करियर बना सकती हैं, लेकिन शादी के बाद या तो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पातीं या फिर अपने करियर को बीच में ही छोड़ देती हैं और फिर, अगर संभव हो तो, अपने परिवार का पालन-पोषण करने के बाद आगे बढ़ती हैं। यह भी एक अपवाद है। शहरी कार्यस्थल में, प्रौद्योगिकी ने कुछ व्यवसायों में युवा महिलाओं को अपने घरों से काम करने में मदद की है, जिसमें रोजाना कार्यस्थल पर जाना जरूरी नहीं है। महामारी का एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। कंपनियां अपने कर्मचारियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने-अपने निवास स्थान से काम करने की सुविधा देती हैं।

महामारी के बाद भी इस प्रथा को अपनाया गया है, जिससे लागत कम हुई है और कंपनियों को मदद मिली है। इस संदर्भ में, प्रौद्योगिकी उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है जो अब घर से काम कर सकती हैं, एक ऐसा विशेषाधिकार जो कई व्यवसायों में उपलब्ध नहीं है। दुर्भाग्य से, बलात्कार के कई मामले कभी दर्ज ही नहीं किए जाते। परिवार बलात्कारी का पीछा करने का साहसी कदम उठाने को तैयार नहीं होते क्योंकि खुलासा करने के दुष्परिणाम और उसके सामाजिक निहितार्थ होते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाओं को प्रकाश में लाया जाए और परिवार न्याय पाने का अपने भीतर साहस जुटाएं। हालांकि यह सच है कि हमारे पास शीघ्र सुनवाई और दोषसिद्धि के लिए प्रक्रियाएं हैं, लेकिन समस्या जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक जटिल है।

परिवार के स्तर पर सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका घर और स्कूल में एक मूल्य प्रणाली को विकसित करना है जो हमारी युवा लड़कियों को समाज में समान भागीदार के रूप में मान्यता दे, उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार दे। उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकती हैं, उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, और उन्हें ऐसा करने का साहस और स्वतंत्रता विकसित करनी चाहिए। बेशक, यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसके लिए सामाजिक दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। माता-पिता को भी इस तरह से सोचने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारे कार्यबल में अन्य देशों की तुलना में महिलाएं कम हैं। इसमें बदलाव होना चाहिए, और बदलाव केवल पुरुष मानसिकता में बदलाव के साथ ही लाया जा सकता है। महिलाएं कुछ व्यवसायों में कहीं ज्यादा कुशल हैं। ऐसे व्यवसायों की पहचान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए जहां महिलाओं को शामिल किया जा सके। हम जानते हैं कि महिलाओं का सबसे बड़ा प्रतिशत स्कूल प्रणाली में है, जहां अधिकांश शिक्षिकाएं हैं। बेशक, इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे पढ़ाने के साथ-साथ अपने घर की देखभाल करने सहित कई काम कर सकती हैं। हमें ऐसे व्यवसायों में भी रास्ते और अवसर तलाशने चाहिए जहां महिलाएं एक ताकत बन सकें। शायद अब समय आ गया है कि हम एक संस्थागत ढांचा स्थापित करें जिसमें युवा लड़कियां, जो अपनी पढ़ाई और पेशे को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें अपनी इच्छाएं व्यक्त करने का विकल्प मिले। उपरोक्त के अलावा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की जांच करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील बनाया जाए कि इन मामलों में अत्यधिक सावधानी बरती जाए और किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण जांच के लिए कोई जगह न हो।

आरक्षण में आरक्षण को लेकर विवाद उचित नहीं

दर्शन 'रत्न' रावण

देश की स्वतंत्रता के समय हर जाति-समुदाय और यहां तक कि राज घराने भी अपनी हिस्सेदारी को लेकर चिंतित थे। इसी मुद्दे को लेकर गोल मेज कान्फ्रेंस हुई। उसी समय बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आरक्षण की मांग रखी थी। इसी के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को हिस्सेदारी के रूप में आरक्षण दिया गया परंतु इसका सही ढंग से वर्गीकरण न होने के कारण समस्या लम्बे समय से ज्यों की त्यों है। वर्गीकरण न होने से देश में आरक्षण प्राप्त एक ही समुदाय में से कोई कमजोर रह गया और कोई ताकतवर बन गया। वर्ष 1964 में तत्कालीन संयुक्त पंजाब और वर्तमान हरियाणा के पूर्व विधायक अमर सिंह धानक ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री पं.जवाहर लाल नेहरू को वाल्मीकि/मजहबी समुदाय को अलग आरक्षण के लिए पत्र लिखा था। इसके उत्तर में पं. नेहरू ने लिखा था कि आपका कहना उचित है, परंतु ऐसा हो न सका। 1975 में ज्ञानी जैल सिंह के मुख्यमंत्री काल में पंजाब कैबिनेट ने फैसला लिया कि चूंकि पंजाब का वाल्मीकि/मजहबी समुदाय आरक्षण का लाभ लेने में पीछे रह गया है, इसलिए इन्हें इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण में अलग से हिस्सा दिया जाए। तब यह आंकड़ा सामने आया था कि पंजाब के दलितों की जनसंख्या का आधा हिस्सा वाल्मीकि/मजहबी समाज है। अत: 25 प्रतिशत आरक्षण में आरक्षण देते हुए इसमें से आधा हिस्सा करके इनके लिए साढ़े 12 प्रतिशत कोटा रखा गया, परंतु किन्हीं कारणों से एक वर्ष बाद यह फैसला लागू हुआ। वर्ष 2006 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी जिस पर समूचे उत्तर भारत के वाल्मीकि/मजहबी समाज में रोष फैल गया और 4 सितम्बर, 2006 को पंजाब बंद की काल दी गई। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने असैम्बली में बिल लाकर पंजाब कैबिनेट के इस फैसले को कानून का रूप दिया परंतु इस कानून को दोबारा चुनौती दे दी गई। इसी मुद्दे को लेकर यह लड़ाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 2022 में शीर्ष अदालत ने वर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह सुझाव दिया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के समक्ष भी ले जाया जाए। अंतत: 1 अगस्त, 2024 को मुख्य न्यायाधीश श्री वाई.बी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटा में कोटा देकर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। भाजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि,''सबको लाभ मिलना चाहिए। मेरे घर के सामने मेरा ही एक दूसरा आदिवासी भाई पत्थर तोड़ रहा है।'' सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले को लेकर कुछ अगड़े दलित संगठनों तथा राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताते हुए इसे एस.सी./एस.टी. अधिकारों का हनन बताया और इसके विरुद्ध भारत बंद की काल दी गई जो सफल नहीं हुई। इसका कारण रहा दलित भाईचारे में आपसी दूरी जो किसी भी देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। इससे केवल सामाजिक दूरी ही नहीं बढ़ती बल्कि इससे देश के विकास और युवाओं की सोच पर भी प्रभाव पड़ता है। 'रामायण' के रचयिता भगवान वाल्मीकि के अनुयायी तथा श्री राम के भक्त इस वाल्मीकि समुदाय के सदस्य मुख्यत: सफाई के पेशे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हर तरह की कठिन परिस्थितियों में अपने प्राण जोखिम में डाल कर अपना कर्त्तव्य निभाया है। इसीलिए पहले ज्ञानी जैल सिंह, फिर कैप्टन अमरेंद्र सिंह के बाद स. प्रकाश सिंह बादल ने अलग आरक्षण को जारी रखा।

क्या आप तैयार हैं फर्स्ट इंप्रेशन के लिए?

आज के समय में सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेना ही काफी नहीं है। जॉब पाने के लिए प्रोफेशनल एटिकेट्स की समझ-बूझ होना भी बहुत जरूरी है। इसी से आपकी एक इमेज भी बनती है। जब आप इंटरव्यूअर के साथ बैठते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन बनने में महज कुछ सेकंड का समय ही लगता है। इतने ही वक्त में आपके बारे में एक राय बन जाती है। भले ही इस दौरान आप एक भी शब्द न बोलें, लेकिन इंटरव्यूअर आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखकर बहुत कुछ समझ जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अच्छा इंप्रेशन बनाने को लेकर चौकस रहें।

'हाथ' देता है संदेश

एक-दूसरे से हाथ मिलाने के स्टाइल से भी आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को आंका जा सकता है। इसलिए हैंडशेक को कतई हल्के में न लें। किसी व्यक्ति से मुलाकात के दौरान चेहरे पर मुस्कान रखना और आंख मिलाकर बात करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है मजबूती और गर्मजोशी से हाथ मिलाना। इतना ही नहीं, हाथ मिलाते समय आप सामने वाले को उत्साही भी दिखें। यह हैंडशेक सही ढंग से होना चाहिए, यानी न तो सामने वाले का हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ना चाहिए और न ही इसे ढीला छोड़ना चाहिए। आम तौर पर हैंडशेक के दौरान हाथ को दो-तीन बार हिलाना सही माना जाता है।

ड्रेसिंग-ग्रूमिंग पर ध्यान

प्रोफेशनल ड्रेसिंग और सोशल ड्रेसिंग मौके के हिसाब से उपयुक्त होना चाहिए। अगर आप पहली बार जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको यह फर्क समझना होगा। इंटरव्यू के लिए जाने हेतु पुरुषों के लिए डार्क कलर का ट्राउजर और लाइट कलर की फॉर्मल शर्ट ही श्रेष्ठ होती है। हल्की-फुल्की धारीदार शर्ट भी पहन सकते हैं। ऐसे मौके पर पैटर्न या डिजाइन वाले कपड़े पहनने से बचें। महिलाएं स्ट्रेट-कट कुर्ता पहन सकती हैं। चाहें, तो साड़ी भी पहन सकती हैं। मगर ध्यान रहे, इसमें ज्यादा तड़क-भड़क न हो। अगर वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहें, तो स्ट्रेट-कट, वेल फिटिंग ट्राउजर पहन सकती हैं। ऐसे मौकों पर एक्सेसरी व मेकअप के मामले में जितना सिंपल रहें, उतना बेहतर होता है।

रेज्यूमे में कॉपी-पेस्ट नहीं!

रेज्यूमे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का आईना होता है। इसलिए इसको लेकर हमेशा गंभीरता बरतें। कई युवा अपना रेज्यूमे बनाते समय किसी दोस्त के रेज्यूमे को लगभग जस-का-तस कॉपी-पेस्ट कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। कारण यह कि हर व्यक्ति की शख्सियत और खासियत अलग होती है और इसी प्रकार हर जॉब के लिए अलग तरह के रेज्यूमे की जरूरत होती है। अगर कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसके रेज्यूमे को कॉपी-पेस्ट करके आप आईटी सेक्टर में जॉब के लिए आवेदन नहीं कर सकते। रेज्यूमे में आपकी अपनी शख्सियत झलकनी चाहिए। इसमें आपके अनुभव, काम, हॉबी, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स आदि का उल्लेख हो। कोशिश करें कि इसमें स्पेलिंग या ग्रामर की गलतियां बिल्कुल न हों। ऐसी गलतियों से आपके बारे में नकारात्मक इंप्रेशन बनता है। रेज्यूमे बनाने के बाद इसे किसी सीनियर या जानकार को एक बार जरूर दिखा दें ताकि उसमें कोई कमी रह जाने पर उसे दूर किया जा सके।

जॉब पाने के बाद

अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो वर्कप्लेस पर विनम्र और मिलनसार बने रहना कई मायनों में फायदेमंद होता है। शुरूआती दिनों में कोई शिकायत या दूसरों की आलोचना करने से बचें। अपना ध्यान सिर्फ काम पर लगाएं। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। काम के प्रति प्रो-एक्टिव रवैया दिखाकर आप बॉस की नजर में अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल लगभग सभी सक्रिय हैं। मगर ध्यान रहे, अपनी ऑनलाइन इमेज साफ-सुथरी रखना जरूरी है क्योंकि आपके बारे में इंप्रेशन बनाने में इसका भी योगदान होता है।

बाजार के बदलते मिजाज पर रखिए नजर

कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते मार्केट रिसर्च बड़े उद्योग के रूप में उभर रहा है। यहां आपके लिए जॉब के कई अवसर है।

बाजार में किसी भी उत्पाद की लॉन्चिंग से पहले कंपनियों के जेहन में एक बात जरूर होती है कि लोगों को उनका उत्पाद पसंद आएगा या नहीं। लोग क्या पसंद करते हैं? उत्पाद की बिक्री कैसी रहेगी.? इन सवालों के जवाब पाने के लिए कंपनियां बाकायदा मार्केट रिसर्च कराती हैं। फिर मार्केटिंग की रणनीति बनाती हैं। ऐसा कमोबेश सभी कंपनियां करती हैं। यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में मार्केट रिसर्च की अहमियत बढ़ी है क्योंकि बाजार का मिजाज रोज बदल रहा है। किसी भी उत्पाद की लॉन्चिंग में कंपनियों के करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। इसलिए कंपनियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहतीं। किसी प्रोडक्ट या सर्विस की लॉन्चिंग/ रीलॉन्चिंग से पहले वे मार्केट सर्वे का सहारा जरूरी लेती हैं। मार्केट रिसर्च सोसायटी ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में रिसर्च इंडस्ट्री की वर्तमान विकास दर करीब 10 प्रतिशत है। इसमें आगे और विस्तार की उम्मीद बनी हुई है क्योंकि देश में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है।

सर्वे का बढ़ता स्कोप मार्केट रिसर्च कंपनियों की सेवाएं निजी कंपनियों के साथ अब राजनीतिक दल भी खूब लेने लगे हैं। आम तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियां टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी व्यूह रचना और घोषणापत्र तक मार्केट रिसर्च के आधार पर ही तैयार करती हैं। चुनाव पूर्व सर्वे के जरिये जनता का मूड जानने की कोशिश भी की जाती है। टीवी चैनल्स और अखबारों में छपने वाले ओपिनियन पोल और एक्जिट पोल की लोकप्रियता से तो सभी वाकिफ हैं।

कैसे होती है मार्केट रिसर्च?

मार्केट रिसर्चर या एनालिस्ट का कार्य मुख्य रूप से सर्वे और रिसर्च से जुड़ा है। अपने तरीकों से ये प्रोफेशनल बाजार का मूड टटोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल, यह भी एक मार्केटिंग रणनीति है। उत्पाद की लॉन्चिंग से पहले सर्वे कराने से यह पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा में कौन-कौन-से उत्पाद हैं, उनकी कीमत क्या है, बिक्री क्या है? कंपनी की मार्केटिंग रणनीति क्या है? बाजार में नए उत्पान की बिक्री का स्कोप क्या है? साथ ही, कंपनियां यह भी जानना चाहती हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं, उन्हें क्या नया पसंद आएगा आदि। इन सभी सवालों का फीडबैक जुटाने के लिए मार्केट रिसर्चर एक क्वैश्चनेयर नुमा फॉर्म तैयार करते हैं। फिर कंज्यूमर सर्वे कराते हैं। ये सर्वे कई तरह से किए जाते हैं, जैसे टेलिफोन या इंटरनेट के जरिये या फिर ग्राउंड सर्वे। बाद में रिसर्च कंपनियां क्लाइंट कंपनी के लिए एक रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं। मार्केट रिसर्चर के इन्हीं सुझावों के आधार पर आखिरकार कंपनियां अपने उत्पाद या सेवा की लॉन्चिंग करती हैं।

पर्सनल स्किल

मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए आपको डाटा एनालिसिस का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश पर अच्छी पकड़ भी होना जरूरी है। बेहतर सेल्समैनशिप और क्रिएटिव क्वॉलिटी भी रखनी होगी। साथ ही, अगर आप टीमवर्क की भावना और काम के प्रति लगन रखते हैं, तो बेझिझक मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।

जॉब प्रोफाइल

मार्केट रिसर्च का कार्य मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बंटा है: फील्ड वर्क और रिसर्च वर्क। इसलिए यहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए जॉब के अवसर भी खूब हैं। रिसर्च एजेंसीज में आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट, फील्ड वर्क डायरेक्टर, फील्ड सुपरवाइजर आदि पदों पर जॉब पा सकते हैं।

कहां हैं जॉब्स?

मौजूदा समय में कई देशी-विदेशी कंपनियां आपको इस फील्ड में जॉब दे सकती हैं। बड़ी कंपनियों में आपको विदेश में भी काम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकारों के तमाम विभागों में भी मार्केट रिसर्चर की काफी मांग है। टेलीकॉम कंपनियों में भी जॉब की संभावनाएं हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंसल्टेंसी का विकल्प भी खुला है। अगर चाहें, तो एंटरप्रेन्योर बनकर खुद की रिसर्च एजेंसी भी खोल सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यताएं

मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में काम की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो बीबीए या मार्केटिंग में एमबीए करके यहां एंट्री लें। साइकोलॉजी, सोश्योलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएट भी यहां करियर बना सकते हैं। कम्प्यूटर साइंस में ग्रेजुएट के लिए भी यहां करियर स्कोप है। कई संस्थान मार्केट रिसर्च के लिए डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। वहीं, फील्ड वर्क के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है।

सैलरी कितनी?

रिसर्च कंपनियों में हर तरह के प्रोफेशनल्स को काफी आकर्षक सैलरी मिलती है। रिसर्चर या एनालिस्ट लेवल पर शुरूआत में ही 30 से 40 हजार रुपए महीना आसानी से मिल जाते हैं। अनुभव बढ़ने पर यह सैलरी 70 हजार से 1 लाख रुपए के आसपास भी पहुंच सकती है। फील्ड वर्क से जुड़े लोग भी शुरूआत में 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं।

ऑनलाइन एग्जाम से डरें नहीं, अपनाएं ये टिप्स

बैंकों में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं कराने वाली प्रमुख एजेंसियां, जैसे आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई भी कम्प्यूटराइज्ड ऑनलाइन फॉर्मेट में परीक्षा लेना या तो शुरू कर चुकी हैं या ऐसा करने की तैयारी में हैं। ऑनलाइन फॉर्मेट अपनाने पर परीक्षार्थियों और अकादमिक विशेषज्ञों दोनों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि कम्प्यूराइज्ड एग्जाम के कई फायदे हैं मगर कई लोगों ने इस आधार पर इसका विरोध भी किया है कि इससे कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी तक पहुंच और उसमें सिद्धहस्तता के आधार पर विभिन्न परीक्षार्थियों में भेद किया जाता है।

जो युवा इस टेक्नोलॉजी से कम परिचित हैं, वे अन्य मामलों में योग्य होने हुए भी पिछड़ सकते हैं। कई ऐसे युवा भी हो सकते हैं, जो यूं तो कम्प्यूटर का प्रयोग खूब करते हैं लेकिन परीक्षा ऑनलाइन देने के नाम पर असहज हो जाते हैं। यदि आप भी उन लोगों में से हैं, जो ऑनलाइन बैंकिंग एग्जाम को लेकर चिंतित हैं, तो हम आपके लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिनसे आपको निश्चित ही लाभ होगा। ऑनलाइन परीक्षा की तकनीक पर चर्चा करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों बैंकिंग परीक्षाओं को ऑनलाइन करने का फैसला किया गया।

ऑनलाइन का है भविष्य

जो भी हो, ऑनलाइन परीक्षाओं के लाभ इसकी हानियों से ज्यादा हैं और भविष्य तो कम्प्यूटराइज्ड परीक्षाओं का ही है। आगे चलकर तमाम परीक्षाएं इसी फॉर्मेट में होने वाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी तक पेपर-पेन वाली परीक्षाएं देते आए परीक्षार्थियों को शुरू-शुरू में ऑनलाइन परीक्षा थोड़ी असहज लग सकती है लेकिन यह कोई हिमालय लांघने जैसा काम भी नहीं है। वैसे भी, सभी बैंकिंग प्रोफेशनल्स से यह अपेक्षा तो की ही जाती है कि उन्हें कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान हो। तो फिर परीक्षा भी कम्प्यूटर पर ही देने में हिचक कैसी?

परीक्षा के माहौल से परिचित हों

कम्प्यूटराइज्ड बैंक परीक्षाओं की आलोचना का एक आधार यह रहा है कि परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर देने में सहज नहीं हो पाते और समय पर पेपर पूरा नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान खुद परीक्षार्थी के पास ही है। जो युवा बैंकिंग एग्जाम देने का इरादा रखते हैं, वे परीक्षा के इस नए माहौल से खुद को अभ्यस्त करना शुरू कर दें। इससे आप एग्जाम फॉर्मेट, स्टाइल और प्रश्नों की शैली से परिचित हो जाएंगे।

टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं

टेक्नोलॉजी हमेशा से भविष्य का रास्ता बताती आई है। ऑनलाइन बैंक पीओ एग्जाम भी इससे अलग नहीं है। टेक्नोलॉजी से समय और मेहनत की बचत होती है, यह तो सब जानते हैं। सो आप भी इस बात पर फोकस करें कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं और कैसे कम समय व कम मेहनत के साथ पेपर हल कर सकते हैं।

अपनी ताकत और कमजोरी पहचानें

एक बार आप ऑनलाइन परीक्षा की टेक्नोलॉजी और फॉर्मेट से परिचित हो जाएं, तो आप अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान सकते हैं। फिर आप अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मसलन, हो सकता है कि आप कम्प्यूटर पर मैथ्स के प्रश्न तो आसानी से हल कर लें लेकिन स्क्रीन पर इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न पढ़ने और उनके उत्तर देने में आपको दिक्कत हो रही हो। ऐसे में आप मैथ्स के मुकाबले इंग्लिश की तैयारी पर अधिक ध्यान दे सकते हैं।

ऑनलाइन मॉक टेस्ट

कम्प्यूटराइज्ड आरबीआई बैंक एग्जाम्स के आने के बाद से कई कोचिंग सेंटर्स तथा टेस्ट प्रेप वेबसाइट्स ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराती हैं। ये मॉक टेस्ट बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस, फॉर्मेट तथा प्रश्नों की शैली को अच्छी तरह समझने के बाद तैयार की जाती हैं। इसलिए इन्हें हल करने पर आप वास्तविक परीक्षा के अनुभव से अवगत हो सकते हैं। इससे नियत समय में पूरा पेपर हल करने में भी आपको मदद मिलेगी।

शॉर्टकट और ट्रिक्स

बैंकिंग एग्जाम में बैठने वाले परीक्षार्थी मैथ्स और क्वॉन्टिटेटिव एबिलिटी के प्रश्न हल करने के लिए कई तरह के शॉर्टकट तथा ट्रिक्स का इस्तेमाल करते आए हैं। ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड टेस्ट में भी आप ऐसा कर सकते हैं। सच तो यह है कि ऑनलाइन टेस्ट दे चुके कई परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्हें इस फॉर्मेट में पहले से कहीं ज्यादा शॉर्टकट और ट्रिक्स हाथ लगी हैं! आप भी इन शॉर्टकट्स और ट्रिक्स को जानें और इन्हें आजमाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कोलकाता की घटना पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान

नई दिल्ली। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी का माहौल है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि %वह घटना से निराश और भयभीत हैं।% अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया और कहा कि बस, अब बहुत हुआ...। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में कोलकाता की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं; अब समय आ गया है कि भारत इतिहास का सामना करे। महिला अपराधों पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके।

समाजवादी पार्टी जम्मू-कश्मीर में सात सीटों पर लड़ेगी चुनाव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अगले महीने सितंबर में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारेगी। भले ही इससे पार्टी को कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव, जो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। उसके लिये यह चुनाव फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने और दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करने के लिए समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर की सात सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अखिलेश ने जे एंड के में चुनावी तैयारी के लिए जियालाल वर्मा को जम्मू-कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वर्मा ने प्रत्याशियों के नामों की सूची भी अखिलेश यादव को सौंप दी है। आजकल में इस सूची का ऐलान हो सकता है।

अब मोहन भागवत को भी मिलेगी मोदी-शाह जैसी सुरक्षा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसी सुरक्षा मिलेगी। दरअसल, गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत की सुरक्षा को जेड प्लस से बढ़ाकर एएसएल (एडवांस्ड सिक्योरिटी लिएजॉन) में बदल दिया है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख को अभी तक जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने कई जगहों पर मोहन भागवत की सुरक्षा में ढिलाई देखी, जिसके बाद ही उन्होंने नए सुरक्षा प्रोटोकॉल पर काम करना शुरू किया और आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि कई भारत विरोध संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं। उनकी सुरक्षा बढ़ाने जाने को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसकी जानकारी दी गई है।

सिब्बल ने हिमंत के 'मियां मुस्लिम' वाले बयान की आलोचना की

नईदिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के 'मियां मुस्लिम' संबंधी बयान को लेकर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने बुधवार को उनकी आलोचना की। शर्मा ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि वह पक्षपात करेंगे और 'मियां मुस्लिमों' को असम में कब्जा नहीं करने देंगे। वह नगांव में 14 साल की एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना की पृष्ठभूमि में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दलों के कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा में बोल रहे थे। सिब्बल ने कहा कि शर्मा का बयान ''विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक जहर घोलने'' वाला है और इस तरह की टिप्पणी पर चुप नहीं रहा जा सकता। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''हिमंत (असम के मुख्यमंत्री) ने कहा है कि पक्ष लेंगे, मियां मुस्लिमों को पूरे असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। मेरा पक्ष है- पूरी तरह सांप्रदायिक जहर घोलने वाला बयान। कार्रवाई होनी चाहिए। चुप्पी कोई जवाब नहीं है।''

बंगाल में बवाल के बीच बोलीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर बंगाल में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। इसके साथ ही ममता ने कहा कि अगर वह पास नहीं हुआ तो हम राजभवन के बाहर बैठेंगे। इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए और वह इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा आहूत बंद का उद्देश्य बंगाल को बदनाम करना है, यह आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले की जांच को पटरी से उतारने की साजिश है।

राज्यसभा में एनडीए ने पहली बार छुआ बहुमत का आंकड़ा

नईदिल्ली। राज्यसभा में अब सरकार के पक्ष में नंबर गेम होता दिखाई दे रहा है। सत्तारूढ़ राजग राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गया। हाल में हुए उपचुनाव में भाजपा के नौ और सहयोगी दलों के दो सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। नौ के साथ, भाजपा की ताकत 96 तक पहुंच गई है, जिससे उच्च सदन में एनडीए 112 पर पहुंच गया है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले तीन अन्य लोगों में एनडीए के सहयोगी एनसीपी गुट, अजित पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मंच से एक-एक व्यक्ति शामिल था। सत्तारूढ़ गठबंधन को छह नामांकित और एक निर्दलीय सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है।

कांग्रेस का भी एक सदस्य निर्वाचित हुआ, जिससे उच्च सदन में विपक्ष की संख्या 85 हो गई। आपको बता दें कि राज्यसभा में 245 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान में आठ रिक्तियां हैं। इमने चार जम्मू-कश्मीर से और चार मनोनीत शामिल है। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 है। निर्विरोध चुने गए भाजपा उम्मीदवारों में असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धिर्य शील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्जी शामिल हैं।

तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने गए। राकांपा अजित पवार गुट के नितिन पाटिल महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा बिहार से उच्च सदन में पहुंचे। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा, जिसके लिए एनडीए एक दशक से कोशिश कर रहा है, विवादास्पद विधेयकों को पारित कराना आसान बना देगा। पिछले कुछ वर्षों में, विपक्ष की बड़ी संख्या अक्सर विवादास्पद सरकारी विधेयकों को उच्च सदन में रोके रखती थी। उनमें से कुछ को नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस जैसे गुटनिरपेक्ष दलों की मदद से पारित किया जा सकता है।

कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी, तेलंगाना से चुने गए निर्विरोध

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उपचुनाव में तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरंजन ने यहां रिटर्निंग अधिकारी से सिंघवी की ओर से निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उपचुनाव के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जांच के दौरान इसे खारिज कर दिया गया।

सिंघवी मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे और उन्हें मंगलवार को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख पर निर्वाचित घोषित किया गया। सिंघवी ने 19 अगस्त को यहां अपना नामांकन दाखिल किया था। वरिष्ठ वकील ने कहा था कि तेलंगाना में राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामित होना उनके लिए सम्मान की बात है। राज्यसभा उपचुनाव की आवश्यकता के केशव राव के उच्च सदन से इस्तीफे के कारण हुई जब उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के लिए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) छोड़ दी थी।

इस साल की शुरुआत में सिंघवी कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हार गए थे। भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने 27 फरवरी को हुए चुनाव में ड्रॉ के माध्यम से जीत हासिल की, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना राज्य सभा उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी थी। इसको लेकर कई दिनों के अटकलें चल रही थीं। के केशव राव के राज्यसभा से इस्तीफे के मद्देनजर यह सीट खाली हुई थी।

चंपाई सोरेन की जासूसी करने वाले स्पेशल ब्रांच के 2 सब-इंस्पेक्टर दिल्ली में पकड़ाए

■ हिमंता बिस्व सरमा का खुलासा

नईदिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की लंबे समय से जासूसी कर रहे स्पेशल ब्रांच के दो 2 सब-इंस्पेक्टर को दिल्ली में पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के सामने इन दोनों अधिकारियों ने चौंकान वाले खुलासे किए हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि चंपाई सोरेन की जासूसी करने की जिम्मेदारी इन्हें किसने दी। झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा के सह-प्रभारी हिमंता बिस्व सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह खुलासा किया है। इसके बाद झारखंड की राजनीति में एक नया भूचाल आना तय माना जा रहा है।

हिमंता बिस्व सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। झारखंड के एक आदिवासी नेता की इस तरह से जासूसी कराना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि चंपाई सोरेन की लंबे अरसे से जासूसी हो रही है। इन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार, जो एसबी के एडीजी हैं, ने उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। स्पेशल ब्रांच के दोनों सब-इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि चंपाई सोरेन जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तभी ये दोनों उनकी जासूसी किया करते थे। उनकी गतिविधियों को ट्रैक करते रहते थे। हालांकि, हिमंता बिस्व सरमा ने इन दोनों अधिकारियों के नाम उजागर नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये लोग कई और काम से जुड़े हैं, इसलिए उनके नाम का खुलासा करना उचित नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह पहले हिमंता बिस्व सरमा दिल्ली आए थे। तब भी इन दोनों अधिकारियों ने उनका पीछा किया था। एक बार फिर जब वह कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे, तो दोनों उनके पीछे-पीछे दिल्ली आ गए। चंपाई सोरेन के साथ आए लोगों ने दोनों को ट्रैक किया। इसके बाद दोनों को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि चंपाई सोरेन ने कहा है कि वह इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवायेंगे। चंपाई सोरेन का कहना है कि ये दोनों कोलकाता से उसी फ्लाईट में दिल्ली आए, जिसमें वह (झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन) आए थे। यहां उसी होटल में ठहरे, जिसमें वे ठहरे थे। पहले दोनों अधिकारियों ने कहा कि वे पत्रकार हैं, लेकिन बाद में बताया कि वे झारखंड की स्पेशल ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर हैं।

हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि दोनों अधिकारियों की तस्वीरें मेरे पास हैं, लेकिन ये लोग कई और काम करते हैं। ये लोग नक्सल ऑपरेशन समेत कई और ऑपरेशन में लगे हैं, इसलिए उनके कवर को तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है। उनके फोटो भी मैं शेयर नहीं करूंगा। हिमंता ने कहा कि आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री की जासूसी कराई गई हो। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी की निजता का हनन है। अभी दोनों अधिकारी दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। आगे दिल्ली पुलिस क्या करेगी, यह वो जानें, लेकिन जो भी हुआ है, वह सही नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि चाणक्यपुरी के डीसी को इसकी शिकायत की गई थी। अभी दोनों अधिकारी चाणक्यपुरी थाने में हैं। असम के मुख्यमंत्री ने आशंका व्यक्त की है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, की जासूसी कराई गई है, तो यह भी हो सकता है कि चंपाई सोरेन के फोन भी टैप कराए गए होंगे। हिमंता ने कहा कि जब आपने 2 अधिकारियों के फाइव स्टार होटल में ठहरने की फंडिंग की, फ्लाइट में आने की फंडिंग की, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा मामला हो सकता है। हिमंता बिस्व सरमा ने अपने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर लिखा- चंपाई सोरेन जी अभी भी झारखंड राज्य के मंत्री हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि झामुमो-कांग्रेस के लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन चंपाई जी जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता पर स्पूफिंग करने के लिए बड़ा षड्यंत्र भी रचते हैं। झारखंड पुलिस के कुछ अधिकारी पकड़े गये हैं।

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र

नईदिल्ली। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों (डीपीएससी) के पुनर्गठन में देरी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि इससे इसके लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 27 अगस्त को नड्डा को लिखे अपने पत्र में, ओ ब्रायन ने कहा कि 9 जुलाई के राज्यसभा सचिवालय के अनुरोध के अनुसार, विभिन्न दलों को मानसून सत्र शुरू होने से पहले 17 जुलाई से पहले अपना नामांकन जमा करना था। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने 12 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल किया था। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि जब हम राज्यसभा में मिले थे तो मैंने मौखिक रूप से यह मुद्दा उठाया था। आपने मुझे मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि मानसून सत्र की अवधि के भीतर समितियों का गठन कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से, अगस्त बीत जाने के बावजूद भी संसदीय समितियों का गठन नहीं हो सका है। राज्यसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता ने कहा कि इसका हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिनियमित कानून की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मुझे यह बताने की अनुमति दें कि हाल के वर्षों में, गहन जांच के लिए संसदीय स्थायी समितियों या चयन समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

खेल
प्रमुख समाचार

रोहन जेटली संभालेंगे बीसीसीआई सचिव पद

नईदिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेट्री जय शाह अब बीसीसीआई के सदस्य नहीं रहे है। क्रिकेट कम्यूनिटी में उनका रुतबा और अधिक बढ़ गया है। जय शाह निर्विरोध रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चेयरमैन बने है। महज 35 वर्ष की उम्र में आईसीसी चेयरमैन बनकर जय शाह ने नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। वो आईसीसी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनने वाले शख्स बन गए है।

वहीं जय शाह आईसीसी में अब अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में बीसीसीआई में उनकी जगह खाली हो गई है। बीसीसीआई में जय शाह की जिम्मेदारी संभालने के लिए भी नाम तय हो गया है। इस पद की जिम्मेदारी दिवंगत और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली संभालेंगे। जय शाह इस वर्ष एक दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले के पद छोड़ने के बाद इस गद्दी को संभालेंगे। वहीं जय शाह बीसीसीआई सचिव पद पर 2019 से काबिज थे, जो अब उन्हें छोड़ना होगा। इस पद की जिम्मेदारी रोहन जेटली संभालेंगे।

रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है। अब वो अगले बीसीसीआई सचिव बनने की तैयारी में है। क्रिकेट प्रशासन में रोहन जेटली काफी एक्टिवली हिस्सा लेते है। वर्ष 2023 में ही रोहन जेटली दूसरी बार दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने है। इससे पहले वो वर्ष 2020 में भी डीडीसीए के अध्यक्ष थे। रोहन जेटली की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने भारत से ही कानून की डिग्री हासिल की है। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री ली है। रोहन जेटली वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते है। वो कई केस की पैरवी भी करते है। मार्च 2024 में रोहन को दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के स्थायी वकील के तौर पर नियुक्ति मिली है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स लगातार 8वें दिन हरे निशान में बंद

नईदिल्ली। शेयर बाजार में आज लगातार आठवें दिन बढ़त देखने को मिली। आईटी और फार्मा सेक्टर में दमदार तेजी के चलते 50 शेयरों वाला निफ्टी-50 इंट्रा डे ट्रेड में 25,129.60 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। अंत में निफ्टी-50 34.60 अंकों की तेजी के साथ 25,052.35 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं, 30 शेयरों वाला बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 73.80 अंकों या 0.09% की बढ़त के साथ 81,785.56 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ व्यापक सूचकांक भी निचले स्तर पर बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स में आज कुछ ही सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा उछाल दर्ज करने वाला निफ्टी आईटी 1.66% की बढ़त बनाकर बंद हुआ। निफ्टी फार्मा सेक्टर में भी 1.21% का भारी उछाल देखने को मिला। एनालिस्ट्स का मानना है कि निफ्टी की बढ़त के कई कारण हैं।

मोदी ने जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रशंसा की

नईदिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी ने जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले लोगों की बुधवार को प्रशंसा की और कहा कि यह योजना वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने में सर्वोपरि रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है- जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं और इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात एक करने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों खासकर महिलाओं, युवाओं तथा वंचित समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है। वर्ष 2014 में आज के दिन शुरू की गयी प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेश के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है।

एयरटेल की इंडस टावर्स में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी

नईदिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की 2,640 करोड़ रुपये की शेयर बायबैक योजना पूर्ण होने पर इंडस टावर्स में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी होगी। भारती एयरटेल ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, दूरसंचार अवसंरचना क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंडस टावर्स ने 14 अगस्त को 465 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 5.67 करोड़ से अधिक शेयर की पुनर्खरीद शुरू की, जो कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में कुल शेयर की संख्या का करीब 2.107 प्रतिशत है। कंपनी सूचना के अनुसार, ''इंडस टावर्स द्वारा 27 अगस्त 2024 को जारी सूचना के अनुसारज.इंडस टावर्स में कंपनी की शेयरधारिता उसकी चुकता शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक (यानी करीब 50.005 प्रतिशत) हो जाएगी, जो कि शेयर बायबैक योजना के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रासंगिक गतिविधियों के पूरा होने के अधीन है।'' भारती एयरटेल के पास वर्तमान में इंडस टावर्स में 48.95 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एचयूएल को आईटी से मिला 963 करोड़ का डिमांड नोटिस

नईदिल्ली। दैनिक उपयोग की घरेलू वस्तुएं बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) को आयकर विभाग से 962.75 करोड़ रुपये का मांग नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि वह इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। एचयूएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, यह नोटिस ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर (जीएसकेसीएच) को हॉर्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा और वीवा जैसे ब्रांड वाले हेल्थ फूड्स ड्रिंक्स (एचएफडी) व्यवसाय के बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिग्रहण के लिए 3,045 करोड़ रुपये के भुगतान पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की कटौती न करने से संबंधित है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट खारिज करे भारत

डॉ. अश्विनी

रिपोर्ट का कहना है कि भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के एक-चौथाई स्तर तक पहुंचने में 75 साल लगेंगे, यानी एक तरह से भारत के 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प का मजाक उड़ाने की कोशिश की गयी है। विश्व बैंक का दावा है कि यह रिपोर्ट 108 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों पर आधारित है, जिनमें दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी रहती है और जो सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। इस रिपोर्ट ने भारत और इंडोनेशिया की औद्योगिक नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि बहुत अधिक विकास से तेजी से अमीर बनने के बजाय उन्हें लंबी अवधि के लिए धीमी, पर निरंतर वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि मध्यम आय वाले देशों को घरेलू प्रौद्योगिकी विकास का मोह छोड़ना चाहिए और अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित देशों और उनकी कंपनियों, द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए क्योंकि स्वयं की प्रौद्योगिकी विकसित करने का प्रयास संसाधनों की बर्बादी होगा। भारत को आगाह किया गया है कि वह अपनी तकनीक विकसित करने की कोशिश न करे, जैसा मलेशिया और इंडोनेशिया ने किया है।

हैरानी की बात यह है कि भारत की सेमीकंडक्टर नीति और रक्षा आत्मनिर्भरता नीति की भी आलोचना की गयी है। 'द इकोनॉमिस्ट' लिखता है कि भारत द्वारा 509 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों की सूची से बाहर हो गया है। रिपोर्ट में यह कहने की कोशिश की गयी है कि भारत में सरकारी संरक्षण और नयी (विदेशी) फर्मों

के प्रवेश पर पाबंदी से कुशल फर्म भी कुशल नहीं रह पायेंगी। रिपोर्ट कहती है कि जहां एक औसत अमेरिकी फर्म 40 साल में आकार में सात गुना बढ़ जाती है, वहीं भारत में यह केवल दोगुनी होती है।

ऐसा लगता है कि विश्व बैंक इस बात से नाराज है कि भारत सरकार ने टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी की शर्तों को खारिज कर दिया है और आयात शुल्क में पूरी छूट देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के लेखकों को शायद यह बात पता नहीं है कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का दुनिया में अपना एक अलग स्थान है, जिसके कारण देश में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत ऑनलाइन लेन-देन (यूपीआइ) में तेजी से विकास कर रहा है, जिसे खुद इस रिपोर्ट ने भी स्वीकार किया है। यूपीआई को कई देश अपनाने के लिए उत्सुक हैं। चूंकि भारत ने यह तकनीक विकसित कर ली है, इसलिए वह स्विफ्ट जैसी अपनी भुगतान प्रणाली बना सकता है। भारत ने मित्र देशों से रुपये में तेल खरीदने जैसे लेन-देन करना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका और यूरोप के देशों को पसंद नहीं है। भारत में इस तकनीक के विकसित होने के बाद वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां बाजार से लगभग बाहर हो गयी हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र एक और उदाहरण है, जहां भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित कर पीएसएलवी और चंद्रयान जैसी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान बनाकर भारत चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। जिस लक्ष्य के लिए अमेरिका को 166 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे महज 615 करोड़ रुपये में हासिल कर लिया। विश्व बैंक को समझना होगा कि पिछले पांच वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है। जब भारत ने इन देशों से अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक मांगी थी, तो इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को लेकर विश्व बैंक का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इससे विकसित देशों के रक्षा बाजार अब सिकुड़ रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट वास्तव में एक मनगढ़ंत लेख है, जिसमें तर्क और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। भारत को ऐसी रिपोर्टों को न केवल खारिज करना चाहिए, बल्कि इस पर विरोध भी दर्ज कराना चाहिए और विश्व बैंक को अपने विशेष दर्जे का दुरुपयोग न करने का सुझाव भी देना चाहिए।

भाजपा संयुक्त मोर्चा की कार्यशाला सम्पन्न

हम सदस्यता अभियान को संगठन महापर्व के रूप में मनाते हैं - किरण सिंह देव

कार्यकर्ता सदस्यता अभियान का लोगो अपने-अपने डीपी में लगा लें

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि भाजपा विश्व में एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर संगठन की कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम होते हैं और उसका परिणाम आज यह है कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप खड़े हैं। मोर्चा के सभी अध्यक्षों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। बीच में कोरोना के कारण और चुनावों के कारण यह हमारा अभियान अब फिर शुरू हो रहा है। पुन: हमको सदस्य बनना है और बनाना भी है। श्री देव भाजपा सदस्यता अभियान के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों के भाजपा मोर्चा पदाधिकारियों की एक वृहत बैठक बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संबोधित कर रहे थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि हम सदस्यता अभियान को संगठन महापर्व के रूप में मनाते हैं। राजनीतिक दल के रूप में हम काम करते हैं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों ने अपना जो वृत्त रखा है, उसमें लक्ष्य का विषय भी रखा। हम ऐसी कार्य योजना बनाने जा रहे हैं। श्री देव ने कहा कि सभी मोर्चा अध्यक्ष इस विषय को दो-तीन दिन के अंदर अपनी कार्य योजना का पूरा खाका तैयार कर लें क्योंकि 2 तारीख को प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के सदस्य बनने से यहां से शुरुआत होगी। 4 तारीख से जिलों के सदस्यता अभियान में सभी मोर्चा के उस जिले में रहने वाले सभी पदाधिकारी, कार्यसमिति के सदस्य, एक साथ पूरे 35 जिलों से सदस्यता अभियान की शुरुआत एक साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि दो चरणों में सदस्यता अभियान में किसी भी प्रकार से हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। प्रधानमंत्री के हमारे पास जो कार्यक्रम आते हैं उसको सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखें। उसमें भी इसकी चर्चा जरूर करें और संभव हो तो जिस क्षेत्र में जिस पंचायत में जिस वार्ड में जिस जगह पर हम कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां भी हम इसकी चर्चा करें।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि यह लक्ष्य यूं ही पूरा नहीं होगा। एक जगह पर एक काम बहुत कठिन होता है कि हम उस ऊंचाई को मेंटेन करें ताकि जनता के बीच में भी संदेश अच्छा जाए। चार महीना के बाद हम दोनों प्रकार के चुनाव में जाने वाले हैं, एक नगरीय निकाय चुनाव और दूसरा पंचायत चुनाव। इनमें इस सदस्यता अभियान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम अपने पिछले लक्ष्य को पार करें और इस बार तो सभी मोर्चों को टास्क दिया गया है। इस बार जनप्रतिनिधियों को भी टास्क दिया गया है। भाजपा के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनको भी लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक बूथ में 200 सदस्य अगर हम बनाएंगे तो 23,681 बूथ छत्तीसगढ़ में है। परिवार के हिसाब से अपने परिवारों की गणना करें तो मिनिमम सदस्य होते हैं तो 50 लाख पार कर देंगे तो सारा गणित आपको समझ में आ जाएगा। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। चुनाव हमारे लिए जरूरी है। हमको चारों चुनाव में जाना है और एक लक्ष्य ध्यान में रखकर इस बार आप लोग सदस्यता अभियान कीजिएगा कि हमको रिकॉर्ड बनाना है। छत्तीसगढ़ की पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। श्री देव ने युवा मोर्चा से को निर्देशित है कि वह युवाओं के बीच में जाकर छात्रावास में, कॉलेज में, युवाओं को साथ लेकर बात करना है। भारतीय जनता पार्टी वह राजनीतिक दल है जिसका अलग से अपना संविधान है, अपने अलग से संविधान की व्यवस्थाओं का उसमें आकलन है, किस धारा में हमको क्या करना है कब हमको सदस्यता करना है कितने वर्षों की सदस्यता होगी? सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करके कार्यकर्ता सदस्यता अभियान का लोगो अपने-अपने डीपी में सेट कर लें।

प्रत्येक बूथ में 200 नए सदस्य बनाना है - पवन साय- भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा था कि हम दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। भारत की जीवन पद्धति को हम दुनिया के सामने विस्तृत करेंगे, एक विजन देंगे, यह भाजपा का काम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की बात जब होती है तो केवल सदस्यता की बात नहीं सोचना चाहिए। यह बात हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं, हम कार्यकर्ता बना रहे हैं तो हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि अगर सदस्यता का विषय लेकर हम बूथ इकाई तक जाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता हमारा वार्ड में भी जीत करके आएगा जनपद, जिला पंचायत, निगम में भी आएगा। यह कार्यक्रम इस दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाला है। 30 अगस्त तक शक्ति केंद्र की कार्यशाला होगी। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यता लेकर अभियान की शुरुआत करेंगे। 5 सितंबर को मंडल स्तर पर इसका शुभारंभ करना है। 6 से लेकर 17 सितंबर तक बूथ की सदस्यता सबको करनी है। 19 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक सामूहिक सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक बूथ में हमने टारगेट रखा है और इसलिए 200 नए प्राथमिक सदस्य बनाना है।

संविधान का उल्लंघन करने वाले हमें न सिखाएं : देवलाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी गई चिट्ठी पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बघेल स्वयं कई बार संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर चुके हैं, इसलिए उन्हें संविधान, लोकतंत्र, और कानून व्यवस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने अतीत में कई मौकों पर लोकतंत्र और कानून का मजाक बनाया है और कानूनी प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने कहा, बघेल का आरोपियों का समर्थन करना और उनके पक्ष में भीड़ के साथ खड़े होना कहां संविधान में लिखा है? उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और भूपेश बघेल संविधान और लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव बेहद व्यापक है। उन्होंने कहा, साय जी ने संगठन, मंत्री, विधायक, सांसद और अब मुख्यमंत्री के रूप में दशकों तक सेवा की है। उनका कद बहुत बड़ा है और उन्हें उन लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, जो खुद असंवैधानिक कृत्यों में लिप्त हैं।

1 सितंबर से मनाया जाएगा साक्षरता सप्ताह

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों को कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के दिए निर्देश, बेस्ट प्रैक्टिसेस की मांगी रिपोर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1-8 सितम्बर 2024 के बीच आयोजित होने वाले देशव्यापी साक्षरता सप्ताह और 8 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों से कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, सिद्धार्थ कोमल सिंह पदरेशी ने इस कार्यक्रम की सफलता में सभी जिलों के कलेक्टरों से व्यक्तिगत भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के समापन के पश्चात, एक सप्ताह के भीतर जिलों से इस आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस भेजने की आवश्यकता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आयोजित इस साक्षरता सप्ताह में जनमानस के बीच जागरूकता फैलाने और शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिलों से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दें और इसे अधिक रोचक बनाने के लिए नए और प्रभावी तरीकों को अपनाएं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह पदरेशी ने कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया है कि वे इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार में कोई कसर न छोड़ें, ताकि यह आयोजन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और शिक्षा के प्रति जनसमुदाय में जागरूकता और रुचि बढ़ाई जा सके।

बाबू भैया की कलम से ✍

महादेव एप बन्द कराने का क्या प्रदेश सरकारों में दम नहीं

हमारे हिन्दू सनातनी लोगों के आराध्य भगवान भोले शंकर महादेव के नाम को छत्तीसगढ़ के चंद लोगों ने पूंजी के लालच में बदनाम करने का मानों बीड़ा उठा रखा है। महादेव के नाम से सट्टा शुरू किया,महादेव एप सट्टा, हजारों से शुरू हुए इस खेल को इस्पात नगरी भिलाई के युवक ने इसे करोड़ों का अवैध व्यापार बना दिया। लगभग एक करोड़ चालीस लाख की आबादी के हमारे शांत प्रदेश में मुट्ठी भर युवाओं ने तूफान खड़ा कर दिया है। प्रदेश की दो सरकारें इसकी चपेट में हैं। बन्द करने का उपाय नहीं सूझ रहा है। अधिकारों के होते हुए, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। कांग्रेस सरकार भी असहाय थी। वर्तमान भाजपा सरकार भी है। सट्टेबाज इनकी पकड़ के बाहर दुबई में अपनी असीमित पूंजी के बल पर बड़े बड़ों को अपने हाथों में खिला रहा है। तीन संचालकों का तो नाम जाहिर है, जो दुबई से इस काले धंधे को बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ना जाने कितने ऐसे और नाम होंगे जो संचालकों के सहायक बने बैठे हैं,और इनके पकड़े जाने के बाद मामला सम्हालने तैयार बैठे हैं। देश के अन्य राज्यों में भी यह कार्य फैल चुका है। पेड़ की शाखाओं की तरह बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े लोग इनके क्लाइंट हैं। कहा जा रहा है कि यह इसलिए सम्भव हो पा रहा है क्योंकि संबंधित अधिकार सम्पन अधिकारियों से लेकर अदना कर्मचारी जो सिस्टम में बैठे हैं, उनमे से अधिकांश इनकी पूंजी के नीचे दबे हैं। इतनी जटिल समस्या है, यह इससे ही समझा जा सकता है कि लगभग 400 लोगों को इस मुद्दे पर गिरफ्तार किया जा चुका है। परन्तु धंधा ना मंदा हो रहा है ना बन्द हो रहा है,बल्कि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करता दिखाई दे रहा है ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने कोई प्रयास नहीं किये। तब की सरकार ने भी राजनीति करने के साथ कईयों को गिरफ्तार भी किया,कईयों पर नकेल भी कसी। केंद्र सरकार से भी मदद मांगी। वर्तमान भाजपा सरकार ने तो बंद करने के प्रयासों के साथ इस पर बड़ी राजनीति खेलने की कोशिश की है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर शंका की सुई का मुंह घुमा दिया और कहा महादेव एप सट्टा कांग्रेस की देन है।इसके बड़े नेताओं का परिवार इसमें संलिप्त है। कांग्रेस भी बचाव में आई और कहा भाजपा के लोग शामिल है,उन पर क्यों नहीं कहा जा रहा है। अब तो मामला पूरी तरह राजनीति के रंग में रंग दिया गया है। कभी किसी के सर पर तलवार लटकती दिखाई देती है,तो कभी किसी के सर पर लटकती है। परंतु प्रभावी अंकुश इस मामले में लगे शायद कोई भी यह नहीं चाहता, लोगों को ऐसा लगने लगा है। भाजपा सरकार ने इसे कांग्रेस के खिलाफ बड़ी दूरदर्शी राजनीति का अचूक हथियार बनाने के प्रयास में अपनी स्थानीय पुलिस के ईओडब्ल्यू विभाग से जांच कराई,कुछ परिणाम भी दिखाए। राजनीतिक रूप से बात कुछ बनी नहीं। कुछ लोगों के नाम सामने आये। 16 महीने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इसकी गहन जांच शुरू की। इस प्रकरण की जांच में कांग्रेसी नेताओं,पिछली सरकार के कुछ प्रभावशाली लोग के साथ पुलिस अफसर और प्रोपर्टी डीलर के नाम शामिल हैं। अलग अलग राज्यों से पुलिस ने इस प्रकरण में लगभग 400 आरोपियों को पकड़ा भी है। लोगों को आश्चर्य इस बात पर हैं कि भिलाई-दुर्ग में एक जूस सेंटर चलाने वाला मामूली युवक सौरभ चंद्राकर व रवि उप्पल इसके प्रमोटर कैसे बने और 11 हजार करोड़ का साम्राज्य इतने संबंधित विभागों व पुलिस के रहते अब तक कैसे फैला पाए ? आरोपियों में पुलिस के छोटे कर्मचारी भी पकड़ाए हैं।निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि प्रमोटरों को सिस्टम से नो ऑब्जेक्शन अनुमति थी। उसी के सहारे वे लोग जब तक बात बिगड़े आन लाइन इस काले व्यापार की जड़ें इतनी गहरी जमा चुके हैं कि अब कोई कुछ बिगाड़ पाए, यह दम फिलहाल किसी में नहीं दिखता। सरकार में भी नहीं,ना इस सरकार में दम है ना पूर्ववर्ती सरकार में था। कल ही एक टीवी डिबेट में भाजपा के एक प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस काले धंधे को बन्द करना कठिन है। उन्होंने कारण भी बताया कि ये महादेव एप वाले ऑनलाइन में 350 प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहें हैं। एक बन्द करो तो दूसर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इस बयान में एक बात स्पष्ट हो रही है कि, वर्तमान भाजपा सरकार भी इस धन्धे को बन्द करने में अपने आपको असमर्थ पा रही है। इसके पहले की सरकार भी असमर्थ थी। इसमें अब दोष किसका है। यह कैसे कहा जा सकता है ? जब सरकारों की क्षमता में नहीं है ,तो आप कांग्रेस सरकार को दोषी कैसे व किस कारण कह रहे हैं। इसी में शंका होती है कि भाजपा की वर्तमान सरकार इस पर राजनीति कर रही है। अकेले कांग्रेस को दोषी करार दे रही है। अगर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार दोषी है तो आज भी महादेव सट्टा बन्द तो नहीं हुआ है। तो क्या अपने आपको भी दोषी नहीं मानना चाहिए। अब वर्तमान सरकार सीबीआई को मामला सौंप कर यह बताने का प्रयास कर रही है कि वर्तमान सरकार महादेव एप के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। लेकिन सीबीआई की जांच का दायरा इस बात पर है कि कौन कौन इसमें संलिप्त हैं या थे। उनके नाम सामने आएं। वैसे भी भाजपा बहुत पहले से ही पूर्व मुख्यमन्त्री और उनके करीबियों पर संदेह की सुई घुमाती रही है। देखिए परिणाम उसके ही अनुरूप आते हैं या निष्पक्ष रूप से सभी नाम सामने आयेंगें, चाहे वे सिस्टम में बैठे वे प्रभावशाली लोग या विभाग ही क्यों ना हों। इन विभागों पर शक की सुई जनता की अदालत में इस कारण घूमती रही है कि इतना बड़ा खेल प्रदेश में धड़ल्ले से होता रहा और वे आराम से कैसे बैठे रहे।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

ध्यान भटकने एआई और रोबोटिक प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं

रायपुर। बस्तर के स्कूलों में एआई और रोबोटिक प्रशिक्षण के सरकार के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जब-जब भाजपा की सरकार आती है तब तब भाजपा की सरकारों के द्वारा शिक्षा व्यवस्था षड़यंत्र पूर्वक बाधिक करने का काम किया जाता है। सुदूर बस्तर में कार्यरत विद्यामितानों को नौकरी से जबरिया निकाल दिया गया है, बस्तर के ज्यादातर स्कूलों में बिजली और इंटरनेट के कनेक्शन नहीं है, प्रदेश के सैकड़ो स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, हजारों स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसा है, नई भर्तियां रोक दी गई है और भाजपा सरकार अपने नाकामी और अपने शिक्षा विरोधी षड्यंत्र पर परदेदारी करने के लिए एआई और रोबोटिक प्रशिक्षण के काल्पनिक कार्यक्रम को प्रचारित कर रही है। सरकार बताये एआई और रोबोटिक प्रशिक्षण के लिये विशेष शिक्षकों की भर्ती कब करने जा रही है? बस्तर के 12000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है, सरकार उनको तो भर नहीं पा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में संचालित मॉडल स्कूलों को निजी क्षेत्र की संस्था डीएवी को बेच दिया था। पूर्ववर्ती भारतीय

मुख्यमंत्री आज राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को करेंगे पुरस्कृत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरूवार 29 अगस्त 2024 को राज्य खेल अलंकरण समारोह में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह करेंगे। कार्यक्रम के अतिविशिष्ट अतिथि केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार के लिए 06, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 06, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 02, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 11, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी वर्ष 2021-22 के लिए 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 हेतु शहीद राजीव पांडेय पुरस्कार के लिए 04, शहीद कौशल यादव पुरस्कार के लिए 07, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए 01, शहीद पंकज विक्रम सम्मान 15, शहीद विनोद चौबे सम्मान के लिए 05 एवं मुख्यमंत्री ट्राफी वर्ष 2022-23 के लिए 24 चयनित खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित किया जाएगा।

तीसरी बार खारिज हुई सोम्या की जमानत याचिका

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका तीसरी बार ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला रिज़र्व रखा गया था। जस्टिस एन के व्यास ने फ़ैसले को सार्वजनिक करते हुए ज़मानत याचिका ख़ारिज किए जाने का फ़ैसला सार्वजनिक किया है। राज्य के उप महाधिवक्ता तथा ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय ने ज़मानत ख़ारिज किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की है। हाईकोर्ट में सौम्या चौरसिया की ओर से पेश ज़मानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ था जिसके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू एवं एक अन्य की ज़मानत याचिका मंज़ूर की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया था कि, आवेदिका के बच्चे छोटे हैं और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लगना है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तथ्य भी रखा गया कि, क़रीब डेढ़ साल से वह जेल में है। कोयला घोटाला मामले में जेल में निरुद्ध निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और ईडी के अनुसार कोल लेव्ही स्कैम के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की ज़मानत आवेदन रायपुर कोर्ट में पेश है।

4 आईएएस अफसरों का तबादला

रायपुर. छत्तीसगढ़ में चार आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस प्रसन्ना आर को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा नीलम नामदेव एक्का को मंत्रालय सचिव, जनक प्रसाद पाठक को बिलासपुर संभाग आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है. आईएएस राजेंद्र कुमार कटारा को वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मिशन संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा में शुरू होंगे निजी एफएम चैनल

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के अंतर्गत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784.87 करोड़ रुपये के अनुमानित आरक्षित मूल्य के साथ तीसरे बैच की आरोही (बढ़ती हुई बोली) ई-नीलामी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा शहर भी शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर एफएम चैनल के वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) के रूप में सकल राजस्व का 4 प्रतिशत लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

नवा रायपुर में बंगले आवंटित, एक मंत्री और 10 अफसर हुए शिफ्ट

रायपुर। नवा रायपुर के अटल नगर सेक्टर 24 में करोड़ों की लागत से मंत्रियों व अफसरों के लिए बंगले बनकर तैयार हैं, लेकिन शिफ्टिंग अभी तक केवल एक मंत्री व 10 अफसरों की हुई है। यहां नेता प्रतिपक्ष व मंत्रियों के 14 बंगले और अफसरों के लिए 78 बंगले है। वर्तमान में केवल कृषि मंत्री रामविचार नेताम ही शिफ्ट हुए है, इन्होंने पिछले दिनों अपने घर में गृहप्रवेश किया। साथ ही मंत्रियों में दयालदास बघेल व लक्ष्मी राजवाड़े को भी आवास आवंटित हो गए है, लेकिन इनकी शिफ्टिंग कब होगी। इसके बारे में कोई पता नहीं है। नवा रायपुर में तैयार इन दिनों बंगलों के रखरखाव में ही हर महीने लाखों रुपये खर्च हो रहे है। नवा रायपुर में शिफ्ट होते ही कामकाज में भी तेजी आएगी, साथ ही अनावश्यक खर्च में भी कमी आएगी। नवा रायपुर में बन रहा सीएम हाउस भी 65 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। सीएम आवास की सुरक्षा के लिए हाइटेक तकनीकी का उपयोग किया गया है। साथ ही प्राइवेट थियेटर, हेल्थ सेंटर, लाइब्रेरी जैसी कई सुविधाएं है। मुख्यमंत्री निवास करीब 8 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है।

लेखक अंबर शुक्ल की हीरक जयंती पर विशेष

अपनी पीड़ा के गान को साहित्य में ढाल दिया

गिरीश पंकज

रायपुर शहर में रहने वाले अधिवक्ता एवं साहित्यकार अंबर शुक्ल अम्बरीश अब 75 वर्ष के हो चुके हैं. 29 अगस्त 1949 को ग्राम सेमरिया में जन्मे शुक्ल अपने समय के प्रतिभाशाली छात्र ने रहे. एनसीसी के प्रतिभाशाली कैडेट रहे, जिन्हें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली भेजा गया था. सक्रिय रूप से वकालत करते हुए उनके मन में यकायक काव्य के संस्कार फूट पड़े. उनके नन्हे पुत्र राहुल की असामयिक मृत्यु के कारण अंबर शुक्ला व्यथित हुए और उसकी स्मृति में एक खंड काव्य राहुल के गीत का सृजन किया. यह बात अब 32 साल पुरानी हो चुकी है. इस पुस्तक की समीक्षा मैंने की थी. मेरा यह सौभाग्य रहा कि उनकी लगभग सभी किताबों की भूमिका मैंने लिखी. अंबर शुक्ला साहित्य की दुनिया में धीरे-धीरे रमते चले गए. राहुल के गीत लिखने के बाद उन्होंने एक धुली मुस्कान नामक काव्य संग्रह प्रकाशित करवाया, जिसमें उनकी अनेक महत्वपूर्ण कविताएं दर्ज हैं जो उनके काव्य व्यक्तित्व के उजले पक्ष को रूपायित करती है. उनकी कविताएं इस समय के किसी भी बड़े रचनाकार की कविताओं से कमतर नहीं है. एक धुली मुस्कान के बाद उनकी लघु कथाओं एवं कहानियों का संग्रह मिट्टी के खिलौने प्रकाशित हुआ. इस कृति के बारे में मैंने पुस्तक की भूमिका में लिखा था कि जैसे प्रेमचंद अपने आसपास के चरित्रों को कथाओं में ढालते हैं, उसी परंपरा का अनुगमन करते हुए अंबर शुक्ल अंबरीश ने भी आसपास के चित्रों को अपनी सार्थक कथाओं में रूपांतरित किया है. भले ही ये कहानियाँ काल्पनिक हों,मगर उनमें यथार्थ के अंश स्पष्ट दीखते हैं. लघु कथाओं के क्या कहने. बेहद मर्मस्पर्शी हैं. व्यंग्य से ओतप्रोत. जिन्हें पढ़ कर मुझे परसाई की लघुकथाओं की याद आ गई. अंबर शुक्ल जी के मानस पटल पर अनेक स्मृतियां आज भी सुरक्षित है. बाल्यावस्था की,किशोरावस्था की, युवावस्था की, जिन्हें पढ़ कर हमें पता चलता है कि कैसे एक गाँव से निकला बालक प्रतिभा के बल पर शून्य से शिखर की ओर बढ़ता चला जाता है. छोटा सा बालक जिसका प्रारंभिक नाम ही मुन्नालाल शुक्ल था, बाद में तब इसी नाम के एक लोकप्रिय विधायक के आग्रह पर अपना नाम बदल देता है. वह अंबर शुक्ल बन जाता है क्योंकि उसे सूरज की तरह चमकना था. सूरज का एक नाम अंबर भी है. बाद में जब ये साहित्य कि दुनिया में रमें तो उपनाम अंबरीश भी रख लिया, अंबरीश नाम भी बहुत अच्छा लगा. इस तरह भी हो गए अंबर शुक्ल अंबरीश. उनकी किताब स्मृति के पंख में उनके अनेक रोचक संस्मरण हैं. जैसे जाको राखे साइयां मार सके ना कोय. बेहद रोमांचक संस्मरण. बाल्य काल में अंबर शुक्ला मरते मरते बचे. बचपन में खेलते खेलते हुए वह एक गड्ढे में गिर गए थे. और उनका शरीर कीचड़ में में फंस गया पूरे गांव में गांव में उनकी तलाश हुई एक कहीं नहीं मिले. अंत में तालाब के कीचड़ में फंसे मिले बेहोश. लोगों को लगा सब कुछ खत्म हो गया. लेकिन और कहा बच्चे की सांस चल रही है. सप्ताह पर इलाज चला और मुन्ना ठीक हो गया. इस संस्मरण को शुक्ला जी ने मनोयोग से लिखा है. सेंट पॉलस स्कूल का संस्मरण भी काफी रोचक है, जहां. एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के रूप में अपनी पहचान बनाई. लेकिन उनका कालजयी सृजन का नाम है,गीता में क्या है. श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में अनेक रोचक जानकारियां इसमें दी गई हैं. गीता के सर्वकालिक संदेश क्या हैं,इस संबंध में शुक्ल जी ने बहुत भावपूर्ण और सटीक टीकाएं की हैं. गीता पर तो वैसे हजारों टिकाएं हुई हैं,लेकिन अंबर शुक्ल जी ने गागर में सागर भरते हुए मात्र 88 पेज की इस पुस्तक में गीता के मर्म को समझा दिया है. अपनी हीरक जयंती मनाने वाले शुक्ला जी शतायु हों, यही कामना हम सभी कर रहे हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.